CMYK

RNI.No. — GUJHIN/2012/45192

सूरत भूमि

हिन्दी दैनिक

संपादक : संजय आर. मिश्रा

वर्ष-10 अंक: 198 ता. 02 फरवरी 2022, बुधवार , कार्यालय:114, न्यु प्रियंका टाउनशीप अपार्टमेंट, डिंडोली, डिंडोली, उधना सूरत (गुजरात) मो. 9327667842, 9825646069 पृष्ठ: 8 कीमत: 2:00 रुपये

ho@suratbhumi.com /Suratbhumi.com /Suratbhumi /Suratbhumi /Suratbhumi /Suratbhumi

संक्षिप्त खबरें

रायबरेली: अपनी इकलौती संसदीय सीट पर साख बचाने की कोशिश में है कांग्रेस

रायबरेली। अमेठी में कांग्रेस को पछाड़ने के बाद, भारतीय जनता पार्टी अब उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार के एकमात्र गढ़ रायबरेली को ध्वस्त करने के लिए पूरे जोर-शोर से जुटी हुई है। अगले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी का लक्ष्य विधानसभा चुनावों में जिले की सभी सीटों पर जीत हासिल करना है। रायबरेली 2019 में कांग्रेस के हिस्से में आई एकमात्र लोकसभा सीट थी, यहां तक कि पार्टी की महत्वपूर्ण अमेठी सीट भी भाजपा के हिस्से में आ गई थी। यहां से स्मृति ईरानी ने तत्कालीन सांसद राहुल गांधी को हराया था। विधानसभा चुनाव 2017 में कांग्रेस को महज दो विधानसभा सीटों- रायबरेली (सदर) और हरचंदपुर- पर जीत मिली थी। कांग्रेस के अदिति सिंह और राकेश सिंह को इन सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि, बाद में दोनों भाजपा में शामिल हो गये और इस बार भाजपा ने इन्हें मैदान में उतारा हैं। कभी कांग्रेस के सिपाही रहे, दोनों विधायक अब उसके खिलाफ ही ताल ठोकेंगे। रायबरेली जिले में छह विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं- बछरावां (आरक्षित), सरैनी, ऊंचाहार, सलोन (आरक्षित), सदर और हरचंदपुर। पिछले चुनाव में बछरावां, सरैनी और सलोन में क्रमशः भाजपा के राम नरेश रावत, धीरेंद्र बहादुर सिंह और दल बहादुर ने जीत हासिल की थी, वहीं ऊंचाहार सीट से सपा के मनोज कुमार पांडे निर्वाचित हुए थे। 2017 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस और सपा ने सहयोगी के रूप में लड़ा था। कांग्रेस का दावा है कि इस निर्वाचन क्षेत्र में जो भी विकास हुआ है, वह संप्रग सरकार के दौरान हुआ है।

क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा

मोबाइल से लेकर हीरा लेना हुआ सस्ता, छाता खरीदना महंगा होगा

नई दिल्ली। कोरोना महामारी की तीसरी लहर के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2022-23 पेश किया। इस बजट में सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया है। बजट में कुछ प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है, जिससे ये प्रोडक्ट महंगे हो गए हैं। वही कुछ प्रोडक्ट्स पर सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी घटाई भी है। ऐसे में आपके मन में भी सवाल होगा कि इस बजट का आपकी पॉकेट पर कितना असर होगा? तो चलिए जान लेते हैं बजट में क्या महंगा-क्या सस्ता हुआ? वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन चार्जर, मोबाइल फोन कैमरा लेंस, ट्रांसफॉर्मर की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कस्टम ड्यूटी में कन्सेशन देने की घोषणा की है। मोबाइल पार्ट के सस्ते होने से मोबाइल के भी सस्ते होने की उम्मीद है।

ज्वैलरी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कट और पॉलिश डायमंड के साथ रत्नों पर कस्टम ड्यूटी को 5% कर दिया है। वहीं सिंपली सोन्ड डायमंड पर अब कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। महंगी होने वाली चीजों की बात करें तो सरकार ने छाते पर ड्यूटी बढ़ाकर 20% कर दी है। यानी इंपोर्टेड छाते महंगे हो जाएंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें नहीं हैं जिन पर असर पड़ा हो। दरअसल, अब 90% चीजों की कीमत ऋूळ तय करता है, लेकिन विदेश से मंगाई जाने वाली वस्तुओं पर इंपोर्ट ड्यूटी का असर रहता है और इसकी घोषणा बजट में की जाती है।

इसलिए पेट्रोल, डीजल, छढत्रृ उठत्रृ और इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स जैसे- शराब, चमड़ा, सोना-चांदी, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, मोबाइल, केमिकल, गाड़ियां जैसी चीजों की कीमतों पर बजट घोषणाओं का असर पड़ता है। सरकार इन पर ही इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाती या घटाती है। कुछ पर एक्साइज भी लगाया जाता है। इंपोर्ट ड्यूटी वह टैक्स है जिसे किसी दूसरे देश से आने वाले सामान (इंपोर्ट) पर वसूला जाता है। इंपोर्ट ड्यूटी कितनी लगेगी, यह सामान की कीमत के साथ-साथ सामान किस देश का है, इसके साथ ही कई अन्य चीजों पर भी निर्भर करता है। इंपोर्ट ड्यूटी को कस्टम ड्यूटी, टैरिफ, इंपोर्ट टैक्स या इंपोर्ट टैरिफ भी कहते हैं।

इंपोर्ट ड्यूटी के दो मकसद होते हैं- सरकार के लिए आय जुटाना और लोकल लेवल पर प्रोड्यूस होने वाले सामान को मार्केट में फायदा दिलाना।

मेरा बजट 2022

GST ने सामानों को महंगा-सस्ता करने की ताकत बजट से छीनी

- 1 जुलाई 2017 से गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) लागू हुआ था।
- GST में 17 तरह के इनडायरेक्ट टैक्स को समाहित कर लिया।
- GST रेट तय करने का अधिकार GST काउंसिल के पास चला गया।
- इससे 'क्या सस्ता-क्या महंगा' वाली सुर्खियां बजट से लगभग गायब हो गईं।
- GST ने सामान और सर्विसेज को महंगा-सस्ता करने की ताकत बजट से छीनी।

लाल पोटली पर सीएम योगी का हमला, बताया क्यों लेकर घूम रहे अखिलेश यादव

लखनऊ। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान में अब सिर्फ नौ दिन ही रह गए हैं। ऐसे में सपा-भाजपा में वाक युद्ध तेज हो गया है। दोनों तरफ से जोरदार हमले हो रहे हैं। मेरठ में मंगलवार को सीएम योगी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर सीधा हमला किया। सीएम योगी ने कहा कि वह (अखिलेश यादव) लाल पोटली लेकर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने संकल्प ले लिया है। सीएम योगी ने लाल पोटली को भी दंगों से जोड़ दिया। योगी ने कहा कि आप कोई संकल्प नहीं ले सकते। जब यहां दंगे हो रहे थे और लोग मारे जा रहे थे तो आप सो रहे थे। सीएम योगी ने लोगों से पूछा कि क्या आपने पिछले 5 साल में कोई दंगा देखा है? 2017 से पहले हर दूसरे दिन दंगे होते थे। क्या आप दंगे कराने वाले और महिला सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले लोगों को वोट देंगे? कोई भी स्वाभिमानी समाज उन तत्वों का समर्थन नहीं कर सकता जो महिला सुरक्षा के लिए खतरा हैं। योगी ने कहा कि 2017 से पहले हर दूसरे दिन दंगे होते थे। युवकों ने विरोध किया तो उनके खिलाफ फर्जी केस दर्ज कर लिया गया। महिला सुरक्षा खतरे में थी। किसान दुखी और आत्महत्या करने को मजबूर थे। पिछले दिनों मुजफ्फरनगर में जयंत चौधरी के साथ संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में अखिलेश यादव ने जेब से एक 'लाल पोटली' निकालकर दिखाई और कहा था कि इसमें अन्न है और इसलिए इसे जेब में लेकर घूम रहे हैं। अखिलेश ने कहा था कि किसानों के हक के लिए आखिरी वक्त तक लड़ेंगे।

बाबा सरकार में महामाफिया राज

बीजेपी में जो जितना बड़ा...: अखिलेश यादव का पीएम मोदी पर पलटवार

लखनऊ। 2012 से 2017 के बीच समाजवादी पार्टी (सपा) की सरकार के दौरान कानून व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की ओर से चलाए जा रहे आक्रामक कैंपेन और पीएम मोदी की ओर से लगाए गए आरोपों पर अखिलेश यादव ने जोरदार पलटवार किया है। सपा अध्यक्ष ने मंगलवार को कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में 'महामाफिया राज' है। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी में जो जितना बड़ा है उसका झूठ भी उतना बड़ा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, "बाबा सरकार में 'महामाफिया राज' है। लखीमपुर के किसानों की हत्या, हाथरस की बेटी के साथ हुई अमानवीयता, गोरखपुर हत्याकांड, इनामी अपराधी का खेलना सरेआम, फरार पुलिस कप्तान व अन्य जघन्य कांड जनता भूल नहीं सकतीङ्गझूठ बोलने की भी एक हद होती है!

भाजपा में जो जितना बड़ा उतना बड़ा उसका झूठ।" पीएम मोदी ने 2012 से 2017 तक यूपी में चली सपा सरकार पर बरसते हुए सोमवार को वर्चुअल रैली में कहा, "पश्चिमी यूपी के लोग कभी नहीं भूल सकते कि जब ये क्षेत्र दंगे की आग में जल रहा था, तो पहले वाली सरकार उत्सव मना रही थी। 5 साल पहले- गरीब, दलित, वंचित, पिछड़ों के घर-जमीन-दुकान पर अवैध कब्जा, समाजवाद का प्रतीक था। लोगों के पलायन की आए दिन खबर आती थी।" अखिलेश राज में दबंगों और दंगाइयों के शासन का आरोप लगाते हुए पीएम ने कहा, "कोई भूल नहीं सकता कि 5 साल पहले यूपी को लेकर क्या चर्चा होती थी? 5 साल पहले- दबंग और दंगाई ही कानून थे, उन्हीं का कहा ही शासन का आदेश था। 5 साल पहले- व्यापारी लुटता था, बेटी घर से बाहर निकलने में घबराती थी और माफिया, सरकारी संरक्षण में खुलेआम घूमते थे।"

राहुल ने आम बजट को जीरो सम बजट करार दिया

सरकार ने युवाओं, किसानों को कोई राहत नहीं दी

नयी दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आम बजट पेश किया। जिसको लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने निशाना साधा और इसे जीरो सम बजट करार दिया। उन्होंने कहा कि इस बजट में वेतनभोगी, मध्यम वर्ग, गरीब और वंचितों, युवा, किसान और एमएसएमई के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि मोदी सरकार के बजट में कुछ नहीं है। मध्य वर्ग, वेतनभोगी वर्ग, गरीब और वंचित वर्ग, युवाओं, किसानों और एमएसएमई के लिए कुछ नहीं है। आपको बता दें कि सरकार ने इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। जिसको कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि भारत का वेतनभोगी वर्ग एवं मध्य वर्ग महामारी, वेतन में चौतरफा कटौती और कमरतोड़ महंगाई के इस दौर में राहत की उम्मीद कर रहा था। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि, टैक्स रिटर्न में अगर कोई गलती हो जाती है तो उसे बाद में सुधारा जा सकता है। वित्त मंत्री ने कहा कि अगर करदाता से सलाना आय की घोषणा करने में कोई गलती हो जाती है तो वह इसे 2 साल में सुधार सकता है।

पीएम मोदी बोले- यह 100 साल के विश्वास का बजट

जनता के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह बजट 100 साल की भयंकर आपदा (कोरोना वायरस वैश्विक महामारी) के बीच विकास का नया विश्वास लेकर आया है। उन्होंने कहा कि यह बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ-साथ आम जनता के लिए कई नए अवसरों का निर्माण करेगा। उन्होंने कहा कि यह बजट 100 साल के विश्वास का बजट है। बजट पर लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। इसका पूरा फोकस गरीबों के कल्याण पर है। इससे रोजगार की संभवानाएं भी बढ़ेंगी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार व झारखंड जैसे राज्यों पर ध्यान दिया गया है। पीएम ने आगे कहा कि ये बजट ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, ज्यादा इंवेस्टमेंट, ज्यादा ग्रोथ और ज्यादा जॉब की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। इससे 'ग्रीन जॉब्स' का भी क्षेत्र खुलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, ऐसे क्षेत्रों के लिए पहली बार देश में पर्वतमाला योजना शुरू की जा रही है। ये योजना पहाड़ों पर ट्रांसपोर्टेशन की आधुनिक व्यवस्था का निर्माण करेगी। जनता-जनार्दन की सेवा का हमारा उत्साह अनेक गुना बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि गरीब का कल्याण इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। हर गरीब के पास पक्का घर हो, नल से जल आता हो, उसके पास शौचालय हो, गैस की सुविधा हो, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर है। पीएम मोदी ने कहा कि 2.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक के एमएसपी की घोषणा सीधे किसानों को हस्तांतरित की जाएगी। किसानों की आय दोगुनी होगी। बजट में एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी और कई नई योजनाओं की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बजट में क्रेडिट गारंटी में रिकॉर्ड वृद्धि के साथ ही कई अन्य योजनाओं का एलान किया गया है। डिफेंस के कैपिटल बजट का 68 फीसदी घरेलू उद्योगों को रिजर्व करने का भी बड़ा लाभ, भारत के एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि भारत के करोड़ों लोगों की आस्था, मां गंगा की सफाई के साथ-साथ किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन पांच राज्यों में गंगा किनारे, प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहन दिया जाएगा। कल भाजपा ने मुझे सुबह 11 बजे बजट और आत्मनिर्भर भारत विषय पर बात करने के लिए निमंत्रित किया है। कल 11 बजे मैं बजट के इस विषय पर विस्तार से बात करूंगा।

जितिन प्रसाद बोले: हमारे प्रत्याशी को जिताएं नहीं तो मैं शक्ल दिखाने लायक नहीं रहूंगा

शाहजहांपुर। ददरौल सीट से भाजपा प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह के समर्थन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने अपील करते हुए कहा कि मानवेंद्र सिंह को रिकॉर्ड अंतर से जीत दिलाएं। तभी मुझे सम्मान मिलेगा, अन्यथा लोग कहेंगे कि मुझे शामिल करने का क्या फायदा। कांग्रेस से भाजपा में शामिल होने के बाद यूपी के केबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने सोमवार को शाहजहांपुर में एक जनसभा में भाजपा प्रत्याशी को जिताने की अपील करते हुए कहा कि इन्हें जिताएं नहीं तो मैं शक्ल दिखाने लायक नहीं रहूंगा। लोग कहेंगे कि मुझे शामिल करने का क्या फायदा। ददरौल सीट से भाजपा प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह के समर्थन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने अपील करते हुए कहा कि मानवेंद्र सिंह को रिकॉर्ड अंतर से जीत दिलाएं। तभी मुझे सम्मान मिलेगा, अन्यथा लोग कहेंगे कि मुझे शामिल करने का क्या फायदा। हम शक्ल दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे।

कन्हैया कुमार पर लखनऊ में फेंकी गई स्याही, कांग्रेस मुख्यालय में घटना के बाद जमकर हंगामा

लखनऊ। मंगलवार को कन्हैया कुमार पर कुछ लोगों ने स्याही फेंक दी। घटना कांग्रेस मुख्यालय पर हुई है। कन्हैया कुमार पर उस वक्त स्याही फेंकी गई जब वह लखनऊ सेंट्रल सीट के कांग्रेस उम्मीदवार सदफ जफर के नॉमिनेशन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। स्याही फेंकने वाला कौन है और क्यों स्याही फेंकी गई यह पता नहीं चल सका है। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि फेंकी गई स्याही नहीं बल्कि एक तरह की एसिड है। हालांकि कन्हैया कुमार पर स्याही नहीं पड़ी। जिस वक्त स्याही फेंकी गई उस दौरान आस-पास खड़े 3-4 युवकों पर कुछ बूंदें पड़ी हैं। कन्हैया कुमार कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। स्याही फेंकने वाले को कांग्रेसियों ने पकड़ लिया और जमकर पिटाई भी की है। घटना के बाद काफी देर तक कांग्रेस मुख्यालय में हंगामा होता रहा। कन्हैया कुमार जिस कांग्रेस प्रत्याशी सदफ जफर के प्रचार के लिए पहुंचे थे वह एक्ट्रेस और सोशल एक्टिविस्ट हैं। लखनऊ सेंट्रल सीट से सदफ जफर चुनावी मैदान में हैं। सदफ जफर उत्तर प्रदेश के लखनऊ की रहने वाली हैं। मौजूदा वक्त में वह एक सोशल एक्टिविस्ट की भूमिका निभाते हुए कांग्रेस से जुड़ी रही हैं। गौरतलब है कि सदफ जफर ने फिल्म निमार्ता मीरा नायर की फिल्म 'ए सूटेबल बॉय' में अभिनेत्री का रोल निभा चुकी हैं। इस फिल्म में उनके अभिनय की खूब तारीफ हुई थी। इस वक्त वह अपने दो बच्चों के साथ लखनऊ में रह रही हैं। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन के दौरान यूपी पुलिस ने उन्हें लखनऊ से गिरफ्तार भी किया था।

अन्नदाता भी तकनीक से लैस: किसान ड्रोन से फसलों पर होगा कीटनाशकों का छिड़काव

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को देश का आम बजट पेश कर रही हैं। अपने बजट भाषण में उन्होंने किसानों की सहूलियत के लिए कई ऐलान किए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि तकनीक का इस्तेमाल खेती में भी होगा, किसान ड्रोन का इस्तेमाल होगा। इससे फसल मूल्यांकन, भूमि अभिलेख, कीटनाशकों का छिड़काव किया जाएगा। इतना ही नहीं उन्होंने किसानों के लिए कुछ अन्य ऐलान भी किए। दरअसल, अपने बजट भाषण में सीतारमण ने कहा कि एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीददारी की जाएगी हुए साल 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया जाएगा। तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में भी सरकार काम करेगी। ऑर्गेनिक खेती पर सरकार का जोर रहगा, किसानों को डिजिटल सर्विस मिलेगी। इसके अलावा सिंचाई, पेयजल सुविधाएं बढ़ाने पर भी जोर रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि गंगा नदी के किनारे पांच किमी चौड़े गलियारों में किसानों की जमीन पर फोकस के साथ पूरे देश में रासायनिक मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। रेलवे छोटे किसानों और उद्यमों के लिए कुशल लॉजिस्टिक्स विकसित करेगा। स्थानीय उत्पाद की सप्लाई चैन बढ़ाने के लिए 'एक स्टेशन, एक उत्पाद' योजना शुरू की जाएगी। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए पीपीपी मोड में योजना शुरू की जाएगी। इन सबके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 44605 करोड़ रुपये की लागत से केन-बेतवा लिंक परियोजना को शुरू करने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने पीएम किसान योजना की राशि को लेकर कुछ नहीं कहा। बता दें कि ड्रोन एक मानव रहित विमान है, जिसे दूर से नियंत्रित तरीके से उड़ाया जा सकता है। इसके खेती में प्रयोग की अपार संभावनाएं होने का दावा किया जाता रहा है ।ड्रोन के टैंक की क्षमता 10 लीटर तक बढ़ाई जा सकती है, जिससे आसानी से खेत में छिड़काव किया जा सकता है। 15 मिनट में करीब एक एकड़ क्षेत्रफल में अच्छी तरह से छिड़काव कर समय की बचत के साथ मजदूरी की बचत हो सकती है।

CMYK

बजट पेश होने के बाद विपक्षी नेताओं से मुलाकात करते दिखे पीएम

नई दिल्ली ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार चौथा आम बजट पेश करने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लोकसभा में बधाई देकर विपक्षी गुट में जाकर विपक्ष के नेताओं के साथ संवाद किया। बजट पेश होने के बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित होने पर पीएम मोदी को तृणमूल कांग्रेस के नेताओं सुदीप बंदोपाध्याय और सौगत राय से सदन के अंदर बात करते देखा गया। राय ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि वह बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को वापस बुलाएं। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और धनखड़ के बीच लंबे समय से विवाद जारी है,पिछले दिनों मामला इतना बिगड़ गया कि बनर्जी ने धनखड़ के आधिकारिक ट्विटर हैंडल को ब्लॉक कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं केरल के के सुरेश और गोवा के फ्रांसिस्को सरदिन्हा से भी बातचीत करते देखा गया। सरदिन्हा ने बताया कि प्रधानमंत्री ने गत वर्ष दिसंबर महीने में गोवा मुक्ति दिवस पर आयोजित समारोह के बारे में उनसे पूछा। कांग्रेस के कुछ ही नेता इस कार्यक्रम में शरीक हुए थे। सरदिन्हा उनमें एक थे। बजट पेश होने के तत्काल बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी सदन से चले गए थे। लेकिन प्रधानमंत्री ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी से गर्मजोशी से मुलाकात की। पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा के साथ भी वह हाथ मिलाते नजर आए। मोदी को जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुक अब्दुल्ला, द्रविड़ मुनेत्र कषगम के दयानिधि मारन, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के एन के प्रेमचंद्रन से भी बात करते और कुशलक्षेम पूछते देखा गया। वाईएसआर कांग्रेस के कृष्ण डी लावू और निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को भी प्रधानमंत्री का अभिवादन करते देखा गया।

1.5 लाख डाकघरों को कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ेगी मोदी सरकार

नई दिल्ली।

बजट 2022-23 में मोदी सरकार डाकघरों में आमूल-चूल बदलाव का खाका लेकर आई है।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार देश के सभी 1.5 लाख डाकघरों को कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने जा रही है।साथ ही इन डाकघरों के खाताधारकों को नेट बैंकिंग, कोर बैंकिंग और एटीएम की सुविधा मिलेगी। पोस्ट ऑफिस के खाता धारक अपने अकाउंट से बैंकों के खाते में भी पैसे भेज सकते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार वित्तीय समावेशन की दिशा में लगातार काम कर रही है।वित्त मंत्री ने कहा, 2022 में शत प्रतिशत 1.5 लाख डाक घरों में कोर बैंकिंग सिस्टम चालू होगा। इससे फाइनेंसियल इन्क्लूजन संभव होगा।ग्राहक नेटबैंकिंग के माध्यम से अपना खाता संचालित कर सकते है। मोदी सरकार की महात्वाकांक्षी योजना बताकर वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार के इस सुविधा के बाद डाक घर के खाते से बैंक खाते में पैसे का ऑनलाइन ट्रांसफर संभव होगा। उन्होंने कहा कि इससे विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सुविधा मिलेगी। किसान और सीनियर सिटीजन इससे ज्यादा लाभ ले सकते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार हाल के वर्षों डिजिटल बैंकिंग और डिजिटल लेनदेन में तेजी से बढ़ोतरी हुई है।इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सरकार स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाते हुए देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की स्थापना करेगी।

केन-बेतवा प्रोजेक्ट पर मेहरबान मोदी सरकार, दिए 1400 करोड़ रुपए

नई दिल्ली । केंद्र की मोदी सरकार ने बजट में केन-बेतवा प्रोजेक्ट के लिए 1400 करोड़ रुपए दे दिए हैं। इसकी घोषणा वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान की है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 44,605 करोड़ रुपए का खर्च होने हैं। केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार के साथ 22 मार्च 2021 को प्रोजेक्ट के सहमति पत्र पर साइन किया था। सरकार का कहना है कि इस परियोजना से बुंदेलखंड क्षेत्र को बहुत फायदा होगा है। अब मोदी सरकार ने बताया है कि इस प्रोजेक्ट से 9.0 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचाई होगी। सरकार का दावा है कि इस प्रोजेक्ट से 62 लाख लोगों को साफ पीने का पानी मिलेगा। इसके साथ ही 103 मेगावॉट पनबिजली और 27 मेगावॉट सौर उर्जा का उत्पादन होगा। केन बेतवा प्रोजेक्ट को पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में नदी जोड़ो योजना के तहत तैयार हुआ था। पहली बार 2005 में इस प्रोजेक्ट को लेकर मप्र सरकार, उत्तरप्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर साइन किए थे। इस समझौते के तहत उत्तर प्रदेश के झांसी से बहने वाली केन नदी को मध्यप्रदेश के भोजपुर में बहने वाली बेतवा नदी से जोड़ा जाना था। केन बेतवा प्रोजेक्ट को लेक कई पर्यावरणविद विरोध में भी रहे हैं। पर्यावरणविदों का मानना है कि नदियों को जोड़ने का काम सरकार का नहीं है, प्रकृति का है।

केंद्र ने मनरेगा के लिए 73,000 करोड़ रुपये आवंटित

नई दिल्ली । केंद्र ने केंद्रीय बजट 2022-23 में ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम मनरेगा के लिए 73,000 करोड़ रुपये आवंटित किए। यह मौजूदा वित्त वर्ष के लिये संशोधित आकलन से 25.51 प्रतिशत कम है। निर्मला सीतारमण ने पिछले साल के बजट में भी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (मनरेगा) के लिए 73,000 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। हालांकि, बाद में काम की अधिक मांग के कारण इस संशोधित कर 98,000 करोड़ रुपये कर दिया गया था। मनरेगा का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक वित्तीय वर्ष में हर परिवार के लिये कम से कम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी प्रदान करना है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से तैयार हों। पहले चरण में यह योजना दो फरवरी 2006 से 200 सबसे पिछड़े जिलों में लागू की गई थी, बाद में इसे एक अप्रैल, 2007 से 113 और 15 मई 2007 से 17 अतिरिक्त जिलों तक बढ़ा दिया गया था। शेष जिलों को एक अप्रैल, 2008 से अधिनियम के तहत शामिल किया गया था। अधिनियम में अब देश के सभी ग्रामीण जिले शामिल हैं।

बीएसएफ ने सीमा से सटे गांव में ड्रोन जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया

जम्मू । पाकिस्तान से लगी सीमा पर रह रहे लोग पड़ोसी देश से होने वाली ड्रोन घुसपैठ पर नजर रखने में बीएसएफ की मदद कर रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने 140 से अधिक ड्रोन जागरुकता कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को भारत-पाक सीमा पर ड्रोन गतिविधियों से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में बताया है। आरएस पुरा, अखनूर और अरनिया सेक्टर में सीमावर्ती बस्तियों में ड्रोन गतिविधियों को लेकर जागरुकता फैलाने वाले कई फ्लेक्स बोर्ड भी लगाए गए हैं।

स्थानीय नागरिक ने कहा कि हम सीमा पर ड्रोन गतिविधियों पर नजर रखते हैं। हमें बताया गया है कि आतंकवादियों के इस्तेमाल के लिए हथियार, गोला-बारूद और नशीले पदार्थ गिराने की खातिर कैसे सीमापार से ड्रोन का संचालन किया जाता है।एक अन्य ग्रामीण एवं पूर्व सैनिक ने कहा कि बीएसएफ के गश्त अभियान और तकनीकी निगरानी के अलावा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोग ड्रोन गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सीमा पर तीसरी आंख बने हैं। बीएसएफ के डीआईजी एसपीएस संधू ने बताया कि बीएसएफ ने अतीत में जम्मू, सांबा और कठुआ जिले के सीमावर्ती इलाकों में 170 से अधिक बस्तियों व स्कूलों में 144 ड्रोन जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

संधू के मुताबिक, बीएसएफ ने सीमा पार से ड्रोन गतिविधियों में इजाफे के बाद अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित गांवों में पिछले साल ड्रोन जागरुकता कार्यक्रम शुरू किए थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से संचालित ड्रोन गतिविधियां सीमावर्ती इलाकों में गंभीर चिंता का सबब बनी हैं,क्योंकि ड्रोन के जरिये आतंकियों के लिए मदद सामग्री गिराए जाने की कई घटनाएं दर्ज की गई हैं।डीआईजी बीएसएफ ने कहा,सीमावर्ती इलाकों में रहे लोगों को ड्रोन के द्वारा खेप गिराए जाने का लाइव दृश्य दिखाया गया। बीएसएफ अधिकारियों के अनुसार, गांवों और स्कूलों में विभिन्न फ्लेक्स बोर्ड भी प्रदर्शित किए गए, ताकि सीमावर्ती इलाकों में किसी भी संदिग्ध ड्रोन गतिविधि की जानकारी देने और उसे नाकाम करने के लिए आबादी के बीच समझ व समन्वय को बढ़ाया जा सके। बीते साल जीपीएस से लैस और दस किलो वजन ढोने में सक्षम कई ड्रोन ने पाकिस्तान से दर्जनों बार हथियार, गोला-बारूद और नशीले पदार्थों के जखीरे गिराए थे, जिन्हें जम्मू सीमा पर बीएसएफ और पुलिस ने जब्त किया था।

मौनी अमावस्या पर हजारो ने सरयू में लगाई डुबकी

प्रतिनिधि बरहज देवरिया मंगलवार को बरहज के सरयू तट पर अमावस्या के पावन पर्व पर ठंड के वावजूद सरयू स्नान करने आए हजारो श्रद्धालुओं की भीड़ दिखने लगी कोहरे व ठंड के कारण चौराहों एवं सरजू तटों पर मात्र इक्का दुक्का लोग ही दिखाई दे रहे थे दिन खिलने पर श्रद्धालुओं का हुजूम उम□ प□ा, नदी के किनारो पर स्नान करने वालो का तांता लगा रहा। प्रशासन के द्वारा अमावस्या के पर्व को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए था । दूर दराज से आये श्रद्धालुओ ने आस्था का पर्व मौनी अमावस्या पर सरयू की पवित्र जल धारा में स्नान कर पूजा अर्चना व दान पुण्य करते हुए आशीर्वाद प्राप्त की ।और मेले में दुकानों से जरूरत के सामानों की खरीददारी करअपने अपने घरों को गए पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी से मेले का समापन शांति पूर्वक हुआ। जबकि समाजसेवी व सपा युवा नेता कमलेश शुक्ला ने अपने कार्यकर्ताओं मंजनाथ यादव, प्रेमचन्द, व महेंद्र यादव के साथ मीडिया से बात कर कहा कि महिला श्रद्धालुओं के स्नान के लिए अलग घाट की व्यवस्था की जायेगी।

कोरोना काल के बाद मुंबई एयरपोर्ट ने 9 महीने में दर्ज की 146 प्रतिशत की ग्रोथ

मुंबई।

मुंबई एयरपोर्ट पर कोरोना महामारी की मार सबसे ज्यादा देखने को मिली. लेकिन अब वित्त वर्ष 2021-22 में एयरपोर्ट पर फिर से रौनक वापस आ गई है. भारतीय एयरपोर्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा कोरोना का प्रभाव मुंबई एयरपोर्ट पर देखने को मिला था. मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या में 76 प्रतिशत तक की गिरावट देखी गई थी. लेकिन इस साल यह भारत में सबसे ज्यादा यात्रियों का स्वागत करने वाला एयरपोर्ट बन गया है. साल 2021 में अप्रैल से दिसंबर के बीच मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या में 146 प्रतिशत व उड़ानों की संख्या में 98 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई. भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के मुताबिक भारतीय एयरपोर्ट्स में ये सबसे ज्यादा बढ़त है. हालांकि साल 2020 में ऐसा नहीं था. उस साल 25 मई को एयरपोर्ट्स को दोबारा खोला गया था. दो महीने के बैन के बाद करीब ढाई महीने बाद एयरपोर्ट को डोमैस्टिक यात्रियों के लिए खोल गया था. हालांकि केंद्र सरकार के बैन हटाने के बाद राज्य सरकार ने कुछ पाबंदियां लगा थी जो लगभग पूरे साल जारी रही थी. अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2021 के बीच लगभग 1 यात्रियों ने ही सफर किया जबकि साल 2019-20 में ये करीब साढ़े 4 करोड़ था. उस दौरान इसमें करीब 76 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी. जबकि दिल्ली बैंगलुरु और हैदराबाद में यह गिरावट 63 से 66 प्रतिशत के बीच दर्ज की गई थी. मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटिड के प्रवक्ता ने बताया, 'साल 2021 एविएशन इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर रहा. मुंबई एयरपोर्ट का टर्मिनल 1 साल 2021 में अक्टूबर में खोला गया था. एयरपोर्ट ने एक लाख यात्री एक दिन में रिकॉर्ड किए. महामारी के बाद ऐसा पहली बार हुआ.'

वित्तमंत्री के द्वारा पेश आम बजट को विपक्षी नेताओं ने गीला पटाखा जैसा बताया

नई दिल्ली ।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश आम बजट पर सत्ता और विपक्ष के बीच घमासान शुरू हो गया है। विपक्ष ने आम बजट के लिए मोदी सरकार को आड़े हाथ लेकर कहा कि मोदी सरकार ने देश के वेतनभोगी वर्ग और मध्यम वर्ग को राहत नहीं देकर उनके साथ विश्वासघात' और युवाओं की जीविका पर आपराधिक प्रहार किया है ।कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बजट पर पहला रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि यह बजट गीला पटाखा जैसा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मोदी सरकार के बजट में कुछ नहीं है। मध्यम वर्ग, वेतनभोगी वर्ग, गरीब और वंचित वर्ग, युवाओं, किसानों और एमएसएमई के लिए कुछ नहीं है।'' वहीं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया,भारत का वेतनभोगी वर्ग एवं मध्यम वर्ग महामारी, वेतन में चौतरफा कटौती और कमरतोड़ महंगाई के दौर में राहत की उम्मीद कर रहा था ।लेकिन वित्तमंत्री और प्रधानमंत्री ने फिर से अपने प्रत्यक्ष कर से संबंधित कदमों से इन वर्गों को बहुत निराश किया है ।उन्होंने आरोप लगाया कि सब वेतनभोगी वर्ग और मध्यम वर्ग के साथ विश्वासघात है ।इसके साथ ही सुरजेवाला ने सवाल किया कि क्या सरकार ने 'क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आय पर कर लगाकर 'क्रिप्टो करेंसी' को बिना विधेयक लाए ही वैध करार दिया है? माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी ने ट्वीट किया, बजट किसके लिए है? सबसे अमीर 10 प्रतिशत भारतीय देश की कुल संपत्ति के 75 प्रतिशत के स्वामी हैं। नीचे के 60 प्रतिशत लोग सिर्फ पांच प्रतिशत संपत्ति के मालिक हैं ।महामारी के दौरान अधिक मुनाफा कमाने वालों पर अधिक कर क्यों नहीं लगाया गया?'' उन्होंने दावा किया ''शहरी रोजगार गारंटी के बारे में कोई घोषणा नहीं ।मनरेगा के लिए आवंटन पिछले साल के बराबर 73 हजार करोड़ रुपये रहा। युवाओं की जीविका पर आपराधिक हमला हुआ है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, ''बेरोजगारी और महंगाई से पिस रहे आम लोगों के लिए बजट में कुछ नहीं है। ममता के अलावा तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डेरेक ओब्रायन ने दावा किया कि बजट से साबित होता है, कि प्रधानमंत्री मोदी किसानों, गरीबों और मध्य वर्ग की परवाह नहीं करते।

सरकार के सबसे अच्छे मित्र हैं। किसानों, मध्य वर्ग, दिहाड़ी मजदूरों, बेरोजगारों की प्रधानमंत्री कोई परवाह नहीं करते। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि क्रिप्टो सहित विश्व करेंसी पर जो टैक्स लगाने की बात कही है, वह एक अच्छा कदम है, क्योंकि इसके जरिए डिजिटल करेंसी को रेगुलेट किया जा सकेगा।

इसी कड़ी में बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि करों की मार से कराह रही जनता को नये वादों से लुभाने का प्रयास बजट में हुआ है, जबकि बढ़ती गरीबी बेरोजगारी और महंगाई पर रोकथाम के कोई उपाय नहीं किए है ।मायावती ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा, संसद में पेश आम बजट नए वादों के साथ जनता को लुभाने के लिए लाया गया है, जबकि गतवर्षों के वादों व पुरानी घोषणाओं आदि के अमल को भुला दिया गया है यह कितना उचित।

संक्षिप्त समाचार

केन्द्र सरकार का बजट किसानों के साथ भारी धोखा-राकेश टिकैत

मुजफ्फरनगर । भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मंगलवार को केंद्र सरकार की ओर से संसद में पेश किए गए बजट को किसानों के साथ भारी धोखा बताया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों को कोई राहत नहीं दी है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने एमएसपी का बजट कम कर दिया है। इससे लगता है कि सरकार एमएसपी पर खरीदारी नहीं करना चाहती है। किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट किया कि, ''किसानों को बजट 2022 में सरकार ने दिया भारी धोखा। किसानों की दो गुनी आय करने, सम्मान निधि, 2 करोड़ रोजगार, एमएसपी, खाद-बीज, डीजल और कीटनाशक पर कोई राहत नहीं। एमएसपी पर फसल खरीद में बजट एलोकेशन से फसलों में होगा घाटा।'' वहीं टिकैत ने सोशल साइट कू पर लिखा, ''आज बजट में मोदी सरकार ने एमएसपी का बजट पिछले साल से काफी कम कर दिया। 2021-22 में एमएसपी पर खरीदी का बजट 248000 करोड़ था जो 2022-23 के बजट में घट कर 237000 करोड़ रह गया,वह भी सिर्फ धान और गेहू की खरीदी के लिए। ऐसा लगता है सरकार दूसरे फसलों की एमएसपी पर खरीदी करना ही नहीं चाहती है।''

सीओएआई ने लंबित मांगों की ओर ध्यान नहीं देने पर निराशा जाहिर की

नई दिल्ली । सीओएआई ने बजट में डिजिटल कनेक्टिविटी पर जोर देने और 5जी के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन से संबंधित घोषणा करने की प्रशंसा की, हालांकि अपनी काफी समय से लंबित मांगों की ओर ध्यान नहीं देने को लेकर निराशा भी जाहिर की। सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने कहा कि दूरसंचार क्षेत्र में लेवी घटाने को लेकर सरकार के साथ वह सतत और सकारात्मक रूप से जुड़े रहने को उत्सुक है। सीओएआई के महानिदेशक ने कहा, 5जी मोबाइल सेवाएं शुरू करने की खातिर 2022 में आवश्यक स्पेक्ट्रम के आवंटन संबंधी घोषणा और डिजिटल कनेक्टिविटी पर जोर दिए जाने से हमें प्रसन्नता है।'' हालांकि सीओएआई ने कहा कि उसकी लंबे समय से चली आ रही मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया जिससे उसे निराशा हुई। उन्होंने बजट को वृद्धि समर्थक बताया जिसमें डिजिटल इंडिया पहल पर और जोर दिया गया है।

एमएसपी गारंटी कानून बने तब जाकर किसानों का भला होगा

नई दिल्ली । केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश किया।बजट पर किसान नेता राकेश टिकैत ने पहली प्रतिक्रिया देकर कहा कि एमएसपी गारंटी कानून बनने के बाद ही किसानों को फायदा होगा। गन्ना बकाया पर बात कर टिकैत ने कहा गन्ना कानून में अगर 14 दिनों में भुगतान नहीं होगा,तब ब्याज देने का प्रावधान है, लेकिन पैसा नहीं मिलता है।पांच सालों से बीजेपी की यूपी में सरकार है, लेकिन फिर भी नहीं किया गया।मार्च महीने से भुगतान बकाया है। बता दें टिकैत केंद्र से लगातार एमएसपी पर कानून लाने की मांग करते रहे हैं।कृषि कानूनों के रद्द हो जाने के बाद भी टिकैत सरकार पर बेहद हमलावर हैं।उन्होंने कहा कि जब तक एमएसपी का कानून नहीं लाया जाएगा तब तक अनाजों की खरीददारी में फर्जीवाड़ा होता रहेगा। इससे किसानों के बजाया केवल व्यापारी, अधिकारी और नेताओं को ही फायदा होगा।

नई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खरीदने मिले 1,525 करोड़ रुपये

नई दिल्ली । नई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें (ईवीएम) खरीदने तथा पुरानी हो चुकी, वोटिंग मशीनों को नष्ट करने के लिए 2022-23 के केंद्रीय बजट में निर्वाचन आयोग को देने के लिहाज से विधि मंत्रालय को 1,525 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। मंत्रालय को लोकसभा चुनावों और मतदाता फोटो पहचान पत्रों के लिए भी बजट में आवंटन किया गया है। केंद्रीय विधि मंत्रालय में विधायी विभाग ही निर्वाचन आयोग और चुनाव संबंधी कानूनों से जुड़े मुद्दे देखने वाली नोडल संस्था के रूप में काम करता है। सख्त प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पुरानी ईवीएम को विशेषज्ञ समिति की निगरानी में नष्ट किया जाता है। एक ईवीएम औसत 15 साल तक चलती है। बजट में निर्वाचन के सहायक मद के तहत कुल 292 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं जिनमें 180 करोड़ रुपये लोकसभा चुनाव के लिए और 18 करोड़ रुपये चुनाव फोटो पहचान पत्रों के लिए हैं।

आज़मगढ़ में 3 को 8 बजे से 4 बजे तक होगा मतदान

आजमगढ़ । जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अमृत त्रिपाठी ने जनपद में आजमगढ़-मऊ स्थानीय प्राधिकारी, निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद के लिए निर्वाचन-2022 हेतु मतदेय स्थलवार माइक्रो आब्जर्वर की नियुक्ति की है। उन्होने बताया कि मतदान दिनांक 03 मार्च 2022 को प्रातः 8:00 बजे से सायं 4:00 बजे तक सम्पन्न होगा। मतदान समाप्ति के उपरान्त सील्ड मतपेटियां राजकीय बालिका इण्टर कॉलेज, आजमगढ़ में बनाये गये स्ट्रांग रूम में जमा की जायेंगी। उन्होने निर्देश दिये हैं कि मतदान के समय कोविड-19 के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराना होगा। मतदान दिवस दिनांक 03 मार्च 2022 को मतदान प्रारम्भ होने से 01 घण्टे पूर्व मतदेय स्थल पर पहुँचना अनिवार्य होगा। मतदेय स्थलों पर वीडियोग्राफी कराना सुनिश्चित करायेगें तथा एएसडी लिस्ट का चिन्हांकन करेगें। उन्होने कहा कि मतदान अभिकर्ता की यदि कोई शिकायत होगी तो उसका निस्तारण कराना सुनिश्चित करेगें। मतदान समाप्ति के उपरान्त नियत प्रारूप पर रिपोर्ट प्राप्त कराकर आयोग से नियुक्त आब्जर्वर से अवमुक्त होकर ही अपने घर को प्रस्थान करेगें। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान के दौरान माइक्रो आब्जर्वर का यह दायित्व होगा कि मतदान के दौरान प्रत्येक महत्वपूर्ण बिन्दु उपलब्ध कराये गये प्रारूप पर अंकित करेगें और ये स्पष्ट निर्देश है कि माईक्रो आब्जर्वर पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी के कार्यो में हस्तक्षेप नहीं करेगें। निर्वाचन कार्यों की अवहेलना करने एवं ड्यूटी में शिथिलता बरतने वाले कार्मिकों के विरूद्ध सरकारी सेवक आचरण नियमावली के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही करने के साथ-साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

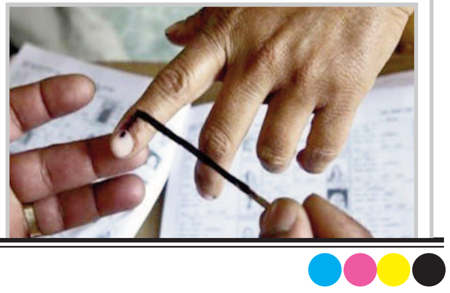

सार समाचार

भारत ने यूक्रेन मुद्दे पर चर्चा के लिए प्रक्रियात्मक मतदान में भाग नहीं लिया

संयुक्त राष्ट्र। भारत ने सोमवार को यूक्रेन सीमा पर हालात के संबंध में चर्चा के लिए होने वाली बैठक से पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में प्रक्रियात्मक मतदान में भाग नहीं लिया। भारत ने रेखांकित किया कि 'शांत और रचनात्मक' कूटनीति 'समय की आवश्यकता' है और अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बड़े हित में सभी पक्षों द्वारा तनाव बढ़ाने वाले किसी भी कदम से बचना चाहिए। यूक्रेन की सीमाओं के पास हजारों रूसी सैनिकों के जमावड़े के बीच यूक्रेन संकट पर चर्चा करने के लिए 15 सदस्यीय परिषद ने एक बैठक की। मास्को की कार्रवाई ने आक्रमण की आशंकाओं को बढ़ा दिया है। हालांकि, रूस ने इस बात से इनकार किया कि वह हमले की योजना बना रहा है। बैठक से पहले परिषद के स्थायी और वीटो- अधिकार प्राप्त सदस्य रूस ने यह निर्धारित करने के लिए एक प्रक्रियात्मक वोट का आह्वान किया कि क्या खुली बैठक आगे बढ़नी चाहिए। अमेरिका के अनुरोध पर हुई बैठक को आगे बढ़ाने के लिए परिषद को नौ मतों की आवश्यकता थी। रूस और चीन ने बैठक के खिलाफ मतदान किया, जबकि भारत, गैबॉन और केन्या ने भाग नहीं लिया। फ्रांस, अमेरिका औरब्रिटेन सहित परिषद के अन्य सभी सदस्यों ने बैठक के चलने के पक्ष में मतदान किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने परिषद में कहा कि नयी दिल्ली रूस और अमेरिका के बीच चल रही उच्च-स्तरीय सुरक्षा वार्ता के साथ-साथ पेरिस में नॉरमैंडी प्रारूप के तहत यूक्रेन से संबंधित घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रही है। तिरुमूर्ति ने कहा, 'भारत का हित एक ऐसा समाधान खोजने में है जो सभी देशों के वैध सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए तनाव को तत्काल कम कर सके और इसका उद्देश्य क्षेत्र तथा उसके बाहर दीर्घकालिक शांति और स्थिरता हासिल करना हो।' उन्होंने रेखांकित किया, ह्यह्यशांत और रचनात्मक कूटनीति समय की मांग है। अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हासिल करने के व्यापक हित में सभी पक्षों द्वारा तनाव बढ़ाने वाले किसी भी कदम से बचा जाना चाहिए।

यूक्रेन को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस, अमेरिका का आमना-सामना

संयुक्त राष्ट्र। यूक्रेन को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस, अमेरिका का आमना-सामना हुआ जहां मास्को यूक्रेन की सीमाओं के पास सेना की तैनाती और पश्चिमी देशों द्वारा हमले की आशंका को लेकर एक खुली बैठक को अवरुद्ध करने के प्रयास में सफल नहीं हो सका। अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस-ग्रीनफील्ड ने रूसी राजदूत वासिली नेबेंजिया के इस आरोप को खारिज कर दिया कि वाशिंगटन संकट पर सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाकर कूटनीति का उपयोग करने की कोशिश कर रहा है। थॉमस ग्रीनफिल्ड ने कहा, 'कल्पना कीजिए कि अगर आपकी सीमा पर 100,000 सैनिक होते तो आप कितने असहज होते।' एक खुली बैठक आयोजित करने पर वोट 10-2 से पारित हुआ। रूस और चीन ने विरोध किया, और तीन सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। वोट को मंजूरी के लिए नौ वोटों की जरूरत थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने एक बयान में कहा कि बल प्रयोग को खारिज करने, सैन्य तनाव कम करने, कूटनीति का समर्थन करने और प्रत्येक सदस्य से जवाबदेही की मांग करने के लिए बैठक एक महत्वपूर्ण कदम थी। उन्होंने कहा कि देशों को अपने पड़ोसियों के खिलाफ सैन्य आक्रमण से बचना चाहिए। रूस ने इस बात से इनकार किया कि वह हमला करने का इरादा रखता है, लेकिन मांग की कि रूस को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) में शामिल नहीं किया जाये। नाटो और अमेरिका ने इन मांगों को असंभव बताया है।

म्यांमार में सेना के सत्ता में आने के बाद से हिंसा बढ़ी

वाशिंगटन । म्यांमार के लिए संयुक्त राष्ट्र की नई विशेष दूत नोलीन हेजर ने दावा किया कि सेना के सत्ता में आने के बाद से हिंसा और क्रूरता बढ़ी है, इसके विरोध में देश में आंदोलन छिड़ गया है। उन्होंने कहा कि सभी पक्षों ने हिंसा को समाधान के रूप में इस्तेमाल करने' को लेकर रुख सख्त लिया है। हेजर ने कहा कि म्यांमार की स्थिति तेजी से अस्थिर होती जा रही है, हवाई हमलों सहित सैन्य अभियानों से नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में लगभग 1,500 नागरिक मारे गए हैं और विस्थापित लोगों की संख्या 2021 के अंत के 3,20,000 के आंकड़े से बढ़कर अब 4,00,000 से अधिक हो गई है।उन्होंने कहा, यह एक फरवरी, 2021 से पहले ही विस्थापित हुए 3,40,000 लोगों के अतिरिक्त है, जब सेना ने आन सांग सू ची को सत्ता से बेदखल कर दिया था। हेजर ने बताया कि म्यांमार की लगभग आधी आबादी वर्तमान में गरीबी के दलदल में है, और 1.44 करोड़ से ज्यादा लोगों को मानवीय सहायता और सुरक्षा की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आसियान के विदेश मंत्री और कुछ नेता पिछले अप्रैल में हुई बैठक में पांच सूत्रीय सहमति को लागू करने के लिए म्यांमार पर दबाव डाल रहे हैं, जिसमें म्यांमा सेना के कमांडर सीनियर जनरल मिन आंग हेइंग भी शामिल हैं। गौरतलब है कि हेइंग ने एक फरवरी 2021 की सुबह सू ची और उनकी सरकार तथा सत्तारूढ़ 'नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी' के शीर्ष सदस्यों को गिरफ्तार करके सत्ता पर कब्जा कर लिया था।

फाइजर से कोरोना टीके की दो-खुराक के लिए आवेदन करने का आग्रह

वाशिंगटन। अमेरिकी नियामक दवा निमार्ता फाइजर से छह महीने से पांच साल तक के बच्चों के लिए अपने कोरोना टीके की दो-खुराक के लिए आपातकालीन उपयोग के लिए आवेदन करने का आग्रह कर रहे हैं, जबकि तीन-खुराक वाले टीके पर आंकड़े की प्रतीक्षा हो रही है। इस कदम का उद्देश्य यथाशीघ्र फरवरी के अंत तक उनके लिए टीकों का रास्ता साफ करना है। मामले से जुड़े शख्स ने इसकी जानकारी दी। कंपनी की तरफ से मंगलवार को आवेदन किए जाने की उम्मीद है। फाइजर के शुरूआती आंकड़ों से पता चला है, कि टीका-जो छोटे बच्चों को वयस्कों के टीके की तुलना के हिसाब से दसवें हिस्से में दिया जाता है - सुरक्षित हैं और एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया पैदा करता है। हालांकि पिछले साल फाइजर ने घोषणा की थी कि दो-खुराक वाला टीका दो से पांच साल के बच्चों में कोरोना को रोकने में कम प्रभावी साबित हुआ, और नियामकों ने कंपनी को विश्वास पर अध्ययन में तीसरी खुराक जोड़ने के लिए प्रोत्साहित कर एक और खुराक वयस्कों में बूस्टर खुराक की तरह प्रभावशीलता को बढ़ाएगी।सूत्र ने बताया कि अब, खाद्य एवं औषधि प्रशासन कंपनी को फरवरी में संभावित अनुमोदन के लिए दो-खुराक के आंकड़ों के आधार पर अपना आवेदन जमा करने के लिए प्रेरित कर रहा है, और फिर तीसरी खुराक के अध्ययन से आंकड़े प्राप्त होने के बाद अतिरिक्त प्राधिकरण के लिए फिर आवेदन करने कहा जा रहा है। तीसरी खुराक के अध्ययन के आंकड़े मार्च तक आने अपेक्षित हैं। संवेदनशील नियामक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यक्ति ने नाम न छापने की शर्त पर बात की। उस व्यक्ति ने कहा कि दो-खुराक के टीके की प्रभावशीलता में कमी कोविड-19 के अत्यधिक संक्रामक ओमीक्रोन स्वरूप के उद्भव के कारण अप्रत्याशित नहीं थी।

जापान का एफ-15 फाइटर जेट उड़ान भरने के बाद गायब हुआ

टोक्यो । जापान का एयर सेल्फ-डिफेंस फोर्स एफ-15 फाइटर जेट सोमवार को इशिकावा प्रांत में कोमात्सु एयर बेस से उड़ान भरने के बाद रडार से गायब हो गया।रक्षा मंत्रालय के अधिकारी के हवाले से इसकी जानकारी दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वह अब विमान के लापता होने की पुष्टि करने के लिए कार्रवाई कर रहा है और फाइटर की खोज जारी है।

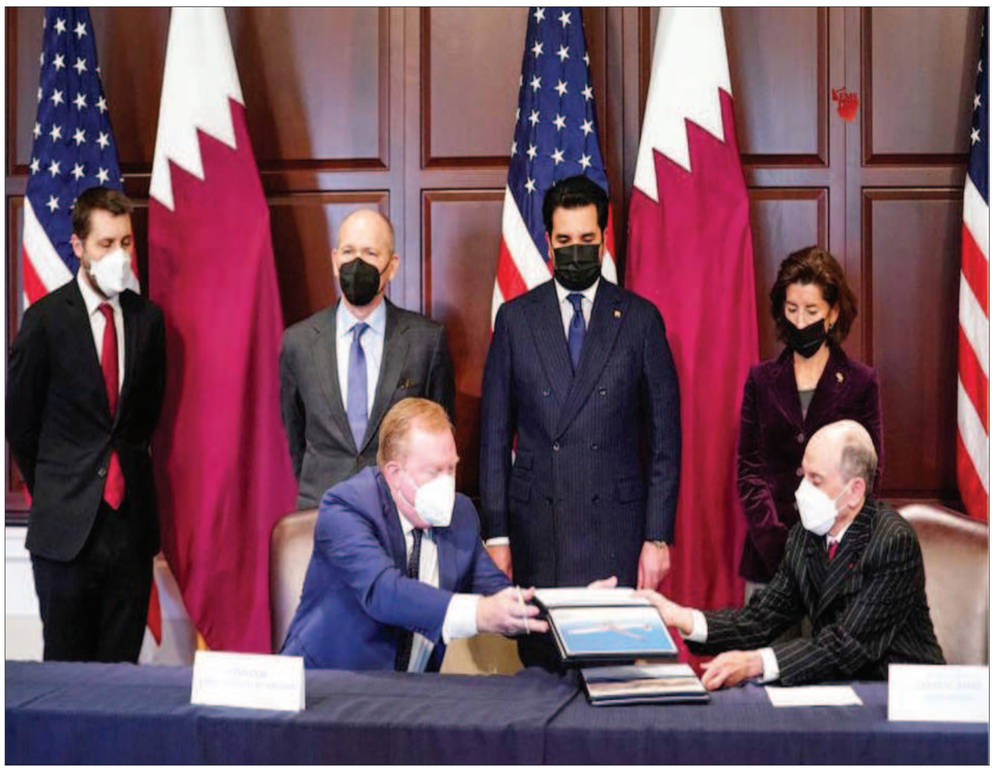

वाशिंगटन में बोइंग कंपनी के प्रेसीडेंट व सीईओ स्टेन डील और कतर एयरलाइंस के सीईओ अकबर अल बकर एक करार पर हस्ताक्षर करते हुए।

रिपोर्ट में कहा गया: लॉकडाउन में पार्टियों का आयोजन नियमों का घोर उल्लंघन, जॉनसन ने माफी मांगी

लंदन। ब्रिटेन में लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और उनके कर्मचारियों द्वारा आयोजित की गई पार्टियों से संबंधित एक जांच में कहा गया है कि ये नियमों का 'घोर उल्लंघन' थीं। इस बीच, जॉनसन ने समूचे घटनाक्रम पर आज माफी मांगी, लेकिन कहा कि उन पर और उनकी सरकार पर भरोसा किया जा सकता है तथा वे चीजों को ठीक कर देंगे।वरिष्ठ लोकसेवक सू ग्रे ने अपनी रिपोर्ट में निष्कर्ष दिया है कि सरकार में नेतृत्व और निर्णय की विफलताएं थीं तथा कुछ चीजों को होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी।' निष्कर्ष पूरी रिपोर्ट के बजाय अपडेट का हिस्सा है। पुलिस के अनुरोध पर निष्कर्षों के प्रमुख अंशों को रोककर रखा गया है, क्योंकि पुलिस मामले में अलग से जांच कर रही है। रिपोर्ट का निष्कर्ष जॉनसन के लिए एक झटका है जिन्होंने पहले कहा था कि नियमों का हर समय पालन किया गया। ग्रे के निष्कर्ष 16 में से केवल चार कार्यक्रमों से संबंधित हैं जिनकी उन्होंने जांच की थी। वर्ष 2020 और 2021 में 12 अन्य पार्टियों को लेकर उनके निष्कर्षों को पुलिस के अनुरोध पर रोक दिया गया है क्योंकि पुलिस मामले में अलग से जांच कर रही है। पुलिस द्वारा जिन कार्यक्रमों के बारे में जांच की जा रही है उनमें जॉनसन के लिए जून 2020 की जन्मदिन की पार्टी और अप्रैल 2021 में प्रिंस फिलिप के अंतिम संस्कार की पूर्व संध्या पर आयोजित दो सभाएं भी शामिल हैं। विपक्षी नेताओं और जॉनसन की पार्टी के कुछ सांसदों ने भी उनके इस्तीफे की मांग की है, लेकिन जॉनसन ने इस मांग को ठुकरा दिया है। इस बीच, जॉनसन ने समूचे घटनाक्रम पर माफी मांगते हुए कहा कि उन पर और उनकी सरकार पर विश्वास किया जा सकता है।

यूक्रेन सीमा पर 1 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक तैनात, रूस करन चाहता हमला

संयुक्त राष्ट्र। (एजेंसी)

यूक्रेन को लेकर रूस का उकसाने वाला रवैया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता का विषय बना हुआ है, जबकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हमले की किसी मंसूबे से इनकार किया है और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने युद्ध कीबात से 28 जनवरी, 2022 को इनकार कर चुके हैं। पुतिन ने यूक्रेन की सीमा के पास एक लाख से अधिक सैन्य बल तैनात किए हैं। उधर, अमेरिका हजारों सैनिक तैनात करने के लिए तैयार है। उसने ब्रिटेन और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) के सहयोगियों से भी पूर्वी यूरोप में हजारों सैनिक तैनात करने को कहा है। पुतिन ने कहा है कि अगर नाटो यूक्रेन को गठबंधन में शामिल करने से मना कर देता है तो वह पीछे हट जाएगा, लेकिन उसकी यह मांग खारिज कर दी गई है। नाटो क्या है? नाटो 1949 में गठित हुआ एक सैन्य गठबंधन है। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ब्रिटेन और

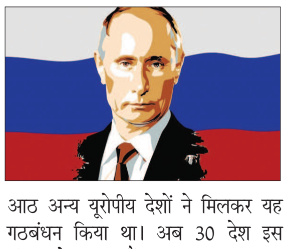

आठ अन्य यूरोपीय देशों ने मिलकर यह गठबंधन किया था। अब 30 देश इस संगठन के सदस्य हैं।

यह गठबंधन संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर काम करता है। नाटो और संयुक्त राष्ट्र के बीच कुछ बातें साझा हैं। ये दोनों ही अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जो सदस्य देशों को वित्तीय मदद देते हैं। इन दोनों पर अमेरिका समेत पश्चिमी शक्तियों का राजनीतिक प्रभाव है, लेकिन दोनों संगठन एक जैसे नहीं है। नाटो का काम आवश्यकता पड़ने पर अपने सैन्य सहयोगियों की मदद से युद्ध लड़ना है, जबकि संयुक्त राष्ट्र शांतिरक्षा, राजनीतिक वार्ता और अन्य साधनों के जरिए युद्ध से बचने का काम करता है। यूक्रेन नाटो में शामिल क्यों होना चाहता है ? यूक्रेन 1992 के बाद से नाटो का साझेदार है।

नाटो ने 1997 में यूक्रेन-नाटो आयोग की स्थापना करके सुरक्षा चिंताओं पर चर्चा के लिए एक मंच मुहैया कराया है। इसके जरिए एक औपचारिक सदस्यता समझौते के बिना नाटो-यूक्रेन संबंध मजबूत हुए थे। नाटो का सदस्य बनाए जाने पर यूक्रेन के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सैन्य समर्थन बढ़ जाएगा, जो रूसी आक्रामकता को रोकने में मददगार हो सकता है। नाटो गैर-सदस्य देशों को समर्थन देने संबंधी सीमाओं को लेकर स्पष्ट है। हालांकि उसने मानवीय आपात स्थितियों के दौरान अफगानिस्तान जैसे गैर-सदस्य देशों का समर्थन किया है, वह किसी गैर-सदस्य देश में सैनिकों को तैनात करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। नाटो की सदस्यता यूक्रेन को यूरोप की ओर अधिक मजबूती से खींचेगी। इससे यह संभावना बढ़ जाएगी कि यूक्रेन यूरोपीय संघ में शामिल हो सकता है, जो यूक्रेन के लिए एक और नीतिगत लक्ष्य है।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की जान खतरे में, दो व्यक्तियों ने बम से उड़ाने की दी धमकी

कॉलेज पार्क (अमेरिका)। (एजेंसी)

अमेरिका में मैरीलैंड और कंसास के एक-एक व्यक्ति पर राष्ट्रपति जो बाइडन को जान से मारने की अलग-अलग धमकियां देने का आरोप लगाया गया है। प्राधिकारियों ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। मैरीलैंड के रयान मैथ्यू कॉनलन (37) और कंसास के स्कॉट रयान मैरीमैन (37) को पिछले हफ्ते गिरफ्तार किया गया था। कॉनलन पर राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के मुख्यालय को बम से उड़ाने की धमकियां देने का भी आरोप लगाया गया है। संघीय प्राधिकारियों ने बताया कि मैरीमैन ने पिछले मंगलवार को अपने गृहनगर में पुलिस को फोन किया और कहा कि वह राष्ट्रपति से मिलने के लिए वाशिंगटन डीसी जा रहा है। जब खुफिया सेवा के एक एजेंट ने उसे गत बुधवार को बुलाया तो मैरीमैन ने कहा कि ईश्वर में उसे वाशिंगटन जाकर 'एक नाग का सिर काटने' के लिए कहा है।

एजेंट ने अदालत में दिए हलफनामे में कहा, 'मैरीमैन ने इससे इनकार किया कि यह नाग अमेरिका का राष्ट्रपति है' एजेंटों ने जब गत बुधवार को मैरीमैन को मैरीलैंड के एक रेस्त्रां की पार्किंग में पकड़ा था तो उसके बैग में हथियार नहीं मिला लेकिन उसमें कारतूस रखे हुए थे। कॉनलन पर एनएसए और एफबीआई को ऐसे कई संदेश भेजने का आरोप है जिनमें राष्ट्रपति को मारने के लिए व्हाइट हाउस को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, मैरीलैंड के फीट मीडे में एनएसए के मुख्यालय को उड़ाने की बात कही गई और एनएसए कर्मचारियों को सामूहिक रूप से गोली मारने का जिक्र किया गया। जांचकताओं ने कॉनलन से जुड़े एक फोन नंबर और मैरीलैंड के पते के आधार परसंदेशों को भेजने वाले का पता लगाया।

म्यांमार की नेता सू ची के खिलाफ चुनाव धोखाधड़ी मामले में सुनवाई 14 फरवरी को होगी

बैंकाक। (एजेंसी)

म्यांमा में अपदस्थ असैन्य नेता आंग सान सू ची के खिलाफ चुनाव धोखाधड़ी मामले में सुनवाई 14 फरवरी को शुरू होगी। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। म्यांमा में फरवरी 2021 को सैन्य तख्तापलट के बाद सेना ने देश में हुए चुनाव में भारी गड़बड़ी के आरोपों में सू ची को गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि स्वतंत्र चुनाव पर्यवेक्षकों का कहना है कि इन आरोपों के संबंध में उन्हें कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं मिले हैं।

अन्य मामलों में सू ची को छह वर्ष के कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। मामले की जानकारी रखने वाले कानूनी अधिकारी ने बताया कि पूर्व नेता पर नवंबर 2020 में हुए चुनाव में केन्द्रीय चुनाव आयोग को प्रभावित करने के आरोप हैं। इस चुनाव में सू ची की पार्टी ह्यनेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसीह्ण से जीत दर्ज की थी। राज्य चुनाव आयोग ने पिछले साल नवंबर में सू ची के खिलाफ चुनाव धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। आयोग के सदस्यों को सैन्य सरकार ने नियुक्त किया था। मामले में सुनवाई राजधानी ने प्यी तॉ में होगी और जुर्म साबित होने पर तीन वर्ष के कारावास का प्रावधान है। पूर्व राष्ट्रपति विन मिंट और राष्ट्रपति कार्यालय के पूर्व मंत्री मिन थू इस मामले में सह-प्रतिवादी हैं। बचाव पक्ष के वकील आरोपों पर सुनवाई के लिए सोमवार को अदालत गए।

अफगानिस्तान में फंसी न्यूजीलैंड की गर्भवती महिला पत्रकार को अपने ही देश में नहीं मिल रही एंट्री

वेलिंगटन। (एजेंसी)

अफगानिस्तान में फंसी न्यूजीलैंड की गर्भवती पत्रकार बेलिस ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने अंततः उन्हें स्वदेश वापसी का प्रस्ताव दे दिया और अब वह घर लौट जाएंगी। न्यूजीलैंड की कोविड-19 संबंधी नीति के कारण बेलिस स्वदेश वापस नहीं जा पा रही थीं। सरकार के इस प्रस्ताव को उसके रुख में परिवर्तन के तौर पर देखा जा रहा है। इसके पहले न्यूजीलैंड के अधिकारियों ने कहा था कि35 वर्षीय बेलिस को स्वदेश वापसी से पहले पृथक-वास के लिए निर्धारितहोटलों में स्थान पाने के लिए फिर से आवेदन करना होगा। लेकिन उप प्रधानमंत्री ग्रांट राबर्टसन ने कहा कि बेलिस को एक कमरे के लिए वाउचर प्रदान किया गया है।

बेलिस ने एक बयान में कहा, 'मैं अपनी बच्ची को जन्म देने के लिए मार्च की शुरूआत में अपने देश न्यूजीलैंड वापस जाऊंगी। हम घर लौटने और इस खास मौके पर परिवार और दोस्तों के बीच रहने को लेकर बहुत उत्साहित हैं।' यह मामला हाल ही में न्यूजीलैंड के लिए शर्मिंदगी का विषय बन गया था। विदेश में न्यूजीलैंड के हजारों नागरिक सैन्य-संचालित पृथक-वास वाले होटलों में स्थान पाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बेलिस ने कहा कि वह न्यूजीलैंड वासियों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि वह सीमा नियंत्रण समाधान के मामले में सरकार को चुनौती देना जारी रखेंगी। अब 25 सप्ताह की गर्भवती बेलिस ने कहा कि उसने पहले लॉटरी-शैली प्रणाली के माध्यम से न्यूजीलैंड में प्रवेशकी असफल कोशिश की। इसके बाद आपातकालीन वापसी के लिए आवेदन किया था, लेकिन इसे भी अस्वीकार कर दिया गया था।

न्यूजीलैंड की पृथक-वास प्रणाली के प्रमुख क्रिस बनी ने कहा कि बेलिस को नया प्रस्ताव दिया गया था, क्योंकि अफगानिस्तान के हालात बेहद खतरनाक थे और वहां आतंकवाद का खतरा था। बेलिस पिछले साल अल जजीरा के लिए काम करते हुए अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी से जुड़ी खबरों को दे रही थीं। वह सितंबर में कतर लौटीं तो उन्हें पता चला कि वह अपने साथी और फ्रीलांस फोटोग्राफर जिम ह्यूलेब्रोक के साथ रहते हुए गर्भवती हुईं। जिम 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' के लिए काम कर रहे थे। कतर में विवाहेतर यौन संबंध अवैध हैं, इससे बेलिस ने कतर छोड़ने की कोशिश की। इसके बाद उन्होंने न्यूजीलैंड वापस जाने का प्रयास किया लेकिनअनुमति नहीं मिली। बेलिस ने नवंबर में अल जजीरा से इस्तीफा दे दिया और साथी ह्यूलेब्रोक के मूल देश बेल्जियम चली गईं, लेकिन वीजा अवधि खत्म होने के कारण उसे देश छोड़ना पड़ा। इसके बाद वह अफगानिस्तान लौट आई, क्योंकि उसके वीजा की अवधि शेष थी।

अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत की नियुक्ति को लेकर क्यों हो रहा विरोध? अमेरिकी सासंद ने जो बाइडेन को लिखा पत्र

इस्लामाबाद/वाशिंगटन। (एजेंसी)

एक अमेरिकी सांसद ने राष्ट्रपति जो बाइडन से पाकिस्तान के मनोनीत राजदूत मसूद खान की राजनयिक परिचयपत्र अस्वीकार करने का आग्रह किया है और उन्हें क्षेत्र में अमेरिका के हितों को कमजोर करने के लिए काम करने वाला और 'आतंकवादियों से सहानुभूति रखने वाला' शख्स करार दिया है। उन्होंने कहा कि खान ने युवाओं को जिहादवादियों का अनुकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया है और विदेशी आतंकवादी संगठनों की प्रशंसा की है। पिछले साल अगस्त तक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के 'राष्ट्रपति' के तौर पर कार्य कर चुके खान को नवंबर में अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत के रूप में नामित किया गया था। रिपब्लिकन सांसद स्कॉट पेरी ने पिछले हफ्ते राष्ट्रपति बाइडन को लिखे एक पत्र में अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत के रूप में खान के मनोनयन के बारे में 'गंभीर चिंता' व्यक्त की।

उन्होंने लिखा, '(पाकिस्तान के प्रधानमंत्री) इमरान खान द्वारा क्षेत्र में अमेरिका के हितों, और हमारे भारतीय सहयोगियों की सुरक्षा की अनदेखी करने वाले आतंकवाद के एक हमदर्द को नामित करने को सिर्फ निर्णय लेने की कमी और अमेरिका के लिये इस्लामाबाद की निरंतर अवमानना के तौर पर ही वर्णित किया जा सकता है।' उन्होंने कहा, 'मुझे इस बात ने प्रोत्साहित किया है कि विदेश विभाग मसूद खान को पाकिस्तान से नए राजदूत के रूप में मंजूरी देने से अभी रुका हुआ है लेकिन यह ठहराव पर्याप्त नहीं है।' उन्होंने पत्र में लिखा, 'मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप मसूद खान द्वारा प्रस्तुत किसी भी राजनयिक परिचय पत्र अस्वीकार करें और पाकिस्तान सरकार द्वारा इस जिहादी को अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत के रूप में स्थापित करने के किसी भी प्रयास को अस्वीकार करें।'

इस्लामाबाद में, डान अखबार ने बताया कि अमेरिकी विदेश विभाग खान के नामांकन को स्वीकार करने में 'असामान्य रूप से लंबा' वक्त ले रहा है और 'देरी ने प्रक्रिया में ठहराव की छाप पैदा कर दी है'। खबर में एक पाकिस्तानी कूटनीतिज्ञ के हवाले से कहा गया है कि मसूद खान के लिए समझौते का अनुरोध विदेश विभाग को नवंबर के दूसरे सप्ताह में भेजा गया था। पाकिस्तान के एक पूर्व विदेश सचिव ने कहा कि आम तौर पर, विदेश विभाग को पहले पाकिस्तानी राजदूतों के लिए कूटनीतिक समझौता जारी करने में चार से छह सप्ताह लगते थे। एक अन्य राजनयिक ने कहा, 'इस बार वे असामान्य रूप से लंबा समय ले रहे हैं।' पेरी ने अपने पत्र में लिखा, 'उन्होंने युवाओं को हिजबुल मुजाहिदीन के पूर्व कमांडर बुरहान वानी जैसे जिहादियों का अनुकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया है, जिसने भारत के खिलाफ कथित जिहाद में जान गंवाई।' उन्होंने कहा कि 2017 में, खान ने हिजबुल मुजाहिदीन के नेता को प्रतिबंधित करने के लिए अमेरिका पर निशाना साधा और, उन प्रतिबंधों को 'अनुचित' कहा था। विदेश कार्यालय (एफओ) के लोगों का हालांकि मानना है कि पीओके के 'राष्ट्रपति' के रूप में खान की पिछले कार्यभार के कारण देरी हुई। मंगलवार को, सवालों के जवाब में, पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता असीम इफ्तिखार ने भारत पर आरोप लगाया कि उसने वाशिंगटन में उसके नामित राजदूत

के नामांकन को मंजूरी देने में अमेरिका द्वारा देरी के बारे में 'फर्जी समाचार' फैलाया। प्रवक्ता ने कहा कि राजदूत खान बहुपक्षीय और द्विपक्षीय कूटनीति दोनों में 40 वर्षों के अनुभव के साथ एक उच्च कुशलता वाले कूटनीतिज्ञ हैं।

सुविचार — बिना उत्साह के आज तक कोई भी महान उपलब्धि पाई नहीं जा सकी है - राल्फ वाल्डो एमर्सन

संपादकीय

बेहतरी के संकेत

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के उद्बोधन और संसद में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश होने के साथ ही बजट सत्र का आगाज हो गया। यह बजट सत्र ऐसे मोड़ पर आयोजित हो रहा है, जब देश तेजी और मजबूती के साथ अर्थव्यवस्था की बहाली की दिशा में बढ़ने को लालायित है। लोग उम्मीदों से भरे हुए हैं। राष्ट्रपति ने अपने उद्बोधन में परंपरागत रूप से सरकार के बेहतर कार्यों का हवाला दिया है। विशेष रूप से महिला सशक्तीकरण और टीकाकरण अभियान की प्रशंसा वाजिब ही है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारा विशाल देश इस मुश्किल दौर में भी बेहतर प्रदर्शन की पूरी कोशिश कर रहा है, पर हमें और बेहतर करने की ओर बढ़ना है। शायद इसी संकल्प के साथ आर्थिक सर्वेक्षण सदन में पेश किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वे में वित्त वर्ष 2022 के लिए 9.2 प्रतिशत जीडीपी विकास दर का अनुमान लगाया है। अनुमान है, भारतीय अर्थव्यवस्था साल 2022-23 के दौरान 8 से 8.5 प्रतिशत की दर से आगे बढ़ेगी। यह बात छिपी नहीं है कि पिछले वर्ष अच्छे नहीं बीते हैं। कोरोना व लॉकडाउन की वजह से बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंची है, इसीलिए उसकी स्थिति सामान्य होने में वक्त लग रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण में पेश आंकड़े निस्संदेह आशा जगाते हैं। कृषि क्षेत्र की विकास दर 3.9 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। यह एक महत्वपूर्ण कामयाबी तो रहेगी ही, लेकिन भारत जैसे कृषि प्रधान देश में हमें अब पांच प्रतिशत से ज्यादा की विकास दर की दिशा में गंभीरता से काम करना चाहिए। बजट में कृषि आय बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास दिखें, तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आज बड़े पैमाने पर मदद की जरूरत है, ताकि देश के कुल विकास में कृषि का योगदान बढ़े। औद्योगिक विकास दर 11.8 फीसदी रहने का अनुमान है और सेवा क्षेत्र 8.2 फीसदी की दर से वृद्धि करेगा। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में विकास दर 10.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है, लेकिन यह बहुत हद तक देश की समग्र माली हालत पर भी निर्भर करेगा। कुल मिलाकर, हमारा आर्थिक सर्वे बुनियादी रूप से बेहतर आर्थिक संकेत दे रहा है। ऐसा लगता है कि आगामी महीनों में हम अर्थव्यवस्था में वांछित तेजी लौटा सकते हैं। सर्वे में महंगाई पर चिंता जताई गई है और उसके लिए बाह्य कारणों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। मतलब ईंधन की कीमतों की ओर इशारा स्पष्ट है। हालांकि, यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह बाह्य कारणों को हावी न होने दे। महंगाई को नियंत्रित रखना इसलिए भी जरूरी है कि क्यों यह एक अकेली ऐसी वजह है, जो अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा सकती है। देश के लिए कच्चा तेल, निवेश, विनिवेश, रोजगार और विकास की चुनौती बरकरार है। ऐसी चुनौतियों से बहुत मजबूती और मनोयोग से निपटने की जरूरत है। सरकार के आर्थिक सलाहकारों की टीम में बार-बार परिवर्तन को रोकना चाहिए। एक विशेषज्ञ टीम को अर्थव्यवस्था को उबारने की जिम्मेदारी दी जाए और उसे काम करने के लिए समय एवं स्वतंत्रता दी जाए, ताकि वह टीम बेहतर परिणाम दे सके। आर्थिक सर्वेक्षण अगर आगामी दिनों में दृढ़ नीतियों और सरकार की दृढ़ आर्थिक सलाहकार टीम को प्रेरित करे, तो आम आदमी के हित में देश की अर्थव्यवस्था के कायाकल्प में आसानी होगी।

आज के कार्टुन

चुनावः भारतीय लोकतंत्र का असाधारण उत्सव

- हृदयनारायण दीक्षित

चुनाव लोकतंत्र का महोत्सव होते हैं, लेकिन अपने देश में मतदान का प्रतिशत प्रायः कम रहता है। देश के पहले लोकसभा चुनाव सन् 1951-52 में मतदान का प्रतिशत 45 ही था। 2019 के लोकसभा चुनाव में यह 67 प्रतिशत हो गया। बेशक प्रगति संतोषजनक है, लेकिन इसे उत्साहवर्द्धक नहीं कहा जा सकता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सभी नागरिकों और राजनैतिक दलों के सदस्यों को कम मतदान पर विचार करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षित और समृद्ध समझे जाने वाले नगरीय-महानगरीय क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत कम होता है। ऐसे क्षेत्रों के लोग सोशल मीडिया पर चुनाव के तमाम पहलुओं पर चर्चा करते रहते हैं, लेकिन मतदान करने प्रायः नहीं जाते। प्रधानमंत्री की यह बात सही है। मतदान से लोकतंत्र मजबूत होता है। मतदान जनतंत्र का विशिष्ट अधिकार है, लेकिन यह एक पवित्र कर्तव्य भी है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी मतदान के प्रतिशत में बढ़ोत्तरी की अपील की है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में हमें संकल्प लेना चाहिए कि मतदाता पीछे न रह जाएं। पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में मतदान का प्रतिशत 67.40 था। मतदान के प्रतिशत में लगातार बढ़ोत्तरी हुई है। मूलभूत प्रश्न है कि मतदान का प्रतिशत अभी भी उत्साहवर्द्धक स्थिति में क्यों नहीं है? क्या विभिन्न दलों के घोषणा पत्र व जनहितकारी आश्वासन मतदाता को मतदान के लिए प्रेरित नहीं करते? अब मतदान के लिए तमाम सुविधाएँ उपलब्ध हैं। पोलिंग बूथ भी घर से बहुत दूरी पर नहीं होते। राजनीतिक दलों के आश्वासन और किये गये काम विभिन्न संचार माध्यमों में सहज-सुलभ हैं, लेकिन मतदान का प्रतिशत नहीं बढ़ता। चुनाव के दौरान सभी दल अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं। सत्ता में आने पर तमाम योजनाओं के पूरा करने के आश्वासन देते हैं। मतदाताओं के सामने विकल्प की कमी नहीं है। दलों का चरित्र भी मजेदार है। अनेक दल विकास के वायदे करते हैं। विकास के इन वायदों पर मतदाता विश्वास नहीं करते। चुनाव में मुफ्त सामग्री देने जैसे वायदे भी होते हैं। चुनाव में मुफ्त वस्तु वितरण के वायदे का प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। कुछ एक दल विचारधारा के आधार पर भी अपने चुनाव अभियान चलाते हैं, लेकिन मतदाताओं के बीच विचार का प्रभाव प्रायः नहीं दिखाई पड़ता है। जाति-मजहब के नाम पर वोट मांगे जाते हैं। जाति और मजहब का उन्माद बढ़ाते हैं। सुधी मतदाता इससे आहत होते हैं और मतदान के प्रति उदासीन हो जाते हैं। 5 राज्यों के चुनाव चल रहे हैं। प्रचार में बेमतलब के सवाल मतदान के लिए प्रेरित नहीं करते। चुनाव में मूलभूत प्रश्नों पर बहस करने का सबसे अच्छा अवसर मिलता है। बेरोजगारी, जन स्वास्थ्य, चिकित्सा व्यवस्था, बिजली, पानी और सड़क जैसे मूलभूत प्रश्नों पर चुनाव में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन ऐसी चर्चा का अभाव है। विकास की आधारभूत संरचना भी चुनाव में बहस का मुद्दा नहीं है। जाति मजहब के आधार पर जारी चुनाव अभियान समाज का वातावरण बिगाड़ते हैं। ऐसे अभियान समाज की आधारभूत एकता पर भी चोट करते हैं। मूलभूत प्रश्न है कि हम वोट क्यों दें? क्या जाति की लामबंदी के लिए वोट दें? क्या राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों की उपेक्षा के बावजूद किसी दल को जाति मजहब के कारण वोट देना ठीक है? भारत के संविधान निर्माताओं ने लम्बी बहस के बाद संसदीय जनतंत्र अपनाया है। यहाँ प्रत्येक वयस्क को मताधिकार है। निष्पक्ष व निर्भीक चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी, 1950 को हुई थी। भारत निर्वाचन आयोग की प्रतिष्ठा सारी दुनिया में है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए आयोग द्वारा प्रत्येक चुनाव में अपील भी की जाती है, लेकिन मतदाता ऐसी अपीलों से प्रेरित नहीं होते। मतदान के गर्भ से ही सरकार का जन्म होता है और विपक्ष का भी। मतदाता ही किसी दल को बहुमत और किसी दूसरे दल या समूह को अल्पमत देते हैं। बहुमत दल को शासन का अधिकार भी मतदाता ही देते हैं और विपक्ष को सरकारी काम की आलोचना का काम भी मतदाता ही सौंपते हैं। आदर्श स्थिति यह है कि मतदाता भारी संख्या में मतदान करें। भारी संख्या से स्पष्ट जनादेश प्राप्त होता है। कम मतदान का अर्थ बड़ा सीधा और सरल है कि दलतंत्र के वायदे मतदाता को भारी मतदान के लिए प्रेरित नहीं करते। राजनीति के प्रति आमजनों की घटती निष्ठा और बढ़ती उपेक्षा कम मतदान का कारण है। लोकतंत्र भारत के लोगों की जीवनशैली है। यहाँ वैदिक काल से लेकर अब तक लोकतंत्र के प्रति गहरी निष्ठा है। संविधान निर्माताओं ने संसदीय लोकतंत्र अपनाया। भारत का संविधान विश्व के अन्य संविधानों से भिन्न है। इसकी उद्देशिका बार-बार पठनीय है। उद्देशिका के अनुसार संविधान की सर्वोपरिता का मुख्य श्रोत 'हम भारत के लोग' हैं। उद्देशिका में सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय समता व बंधुता के राष्ट्रीय स्वप्न हैं। चुनाव अभियान में संविधान की भावना के अनुसार बहस होनी चाहिए। इसी तरह संविधान में नीति-निर्देशक तत्व हैं और मूल कर्तव्य भी हैं। चुनाव अभियान में नीति-निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन पर बहस होनी चाहिए और मूल कर्तव्यों के पालन पर भी। लेकिन चुनाव अभियान में ऐसे उदात्त आदर्श नहीं दिखाई पड़ते। दलतंत्र को भारत की समृद्धि के लिए चुनावी बहस करनी चाहिए। चुनाव भारतीय लोकतंत्र का असाधारण उत्सव है। भारी मतदान से लोकतंत्र मजबूत होता है। सभी दल अपनी विचारधारा के अनुसार चुनाव में हिस्सा लेते हैं। सत्ता की दावेदारी भी करते हैं। चुनाव जनतंत्र के विचार व्यवहार व नीति कार्यक्रम की परीक्षा का अवसर होते हैं। चुनाव में सभी दलों को अपनी विचारधारा के प्रचार का अवसर मिलता है। भारत के कुछ दल जाति, गोत्र, वंश के आधार पर अभियान चलाते हैं। कुछ दलों के संस्थापक प्रायः आजीवन राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्षों के न रहने के बाद उनके पुत्र या पुत्रियाँ पार्टी प्रापर्टी के मालिक हो जाते हैं। इससे लोकतंत्र की क्षति होती है। अधिकांश दलों में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। आश्चर्य की बात है कि जिन दलों में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, ऐसे दल लोकतंत्र का रोना रोते हैं। भारत में क्षेत्रीय विविधता है। समाज में सैकड़ों जातियाँ, उप जातियाँ हैं। समाज जातियों, उप जातियों में विभाजित है। विचारहीन दल उपजातियों जातियों के आधार पर दल बनाते हैं। जाति के आधार पर वोट मांगते हैं। कायदे से सभी दलों को अपनी विचारधारा के अनुसार लोकमत बनाना चाहिए। विचार आधारित राजनैतिक शिक्षण से ही लोकतंत्र की मजबूती है। दरअसल भारत का आमजन राजनैतिक नहीं है। चुनाव के अलावा शेष समय जनता राजनैतिक व्यवहार से मुक्त रहती है। गॉधी जी ने 1895 में लिखा था, ''भारतीय साधारणतया राजनीति में सक्रिय हस्तक्षेप नहीं करते।'' आमजन अपने स्वभाव से ही राजनीति के प्रति उदासीन हैं। भारतवासी केवल चुनाव के दिनों में ही राजनैतिक दलों द्वारा राजनैतिक रूप में सक्रिय होते हैं। विचार से दल बनते हैं। दल विचार को आमजनों तक ले जाते हैं। चुनाव में नीति कार्यक्रम व राष्ट्र संवर्द्धन की चर्चा जरूरी है। लेकिन यहां शत्रु राष्ट्र को भी लाभ पहुँचाने वाली बयानबाजी के दुस्साहस दिखाई पड़ते हैं। भारतीय जनतंत्र बेशक परिपक्व हो रहा है। लेकिन चुनाव अभियानों में शब्द मर्यादा का संयम नहीं है। लोकतंत्र शब्द सौंदर्य से ही मजबूत होता है।

(लेखक, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं।)

भाजपा को दिया अपनों ने झटका

- रमेश सर्राफ धमोरा

पार्टी विद डिफरेंस की टैग लाइन के साथ राजनीति में खुद को अन्य सभी पार्टियों से अलग व श्रेष्ठ बताने वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इन दिनों अपनों द्वारा दिए जा रहे झटकों से उबर नहीं पा रही है। देश के पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। पांचों प्रदेशों में चुनाव लड़ने वाले सभी राजनीतिक दलों द्वारा अपने-अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की जा रही है। इसी दौरान विभिन्न पार्टियों के नेताओं द्वारा दलबदल का खेल भी जोरों से चल रहा है। इस दौरान सबसे अधिक झटका भाजपा को लगा है। कुछ वर्षों पूर्व सत्ता के लालच में भाजपा में शामिल होकर सत्ता का सुख भोगने वाले नेता ऐन चुनाव के वक्त भाजपा छोड़कर दूसरे दलों में शामिल होने लगे हैं। भाजपा के बढ़ते जनाधार को देखकर दूसरे दलों के बहुत से ऐसे मौकापरस्त नेता जिनकी अपने दलों में दाल नहीं गल रही थी, वो सभी भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा ने भी दूसरे दलों से आने वाले नेताओं को भरपूर उपकृत किया। उन्हें विधानसभा व लोकसभा का चुनाव भी लड़वाया तथा चुनाव जीतने पर उनको मंत्री भी बनाया। ऐसे में दलबदल कर पार्टी में आने वाले नेताओं के क्षेत्रों में वर्षों से भाजपा के लिए काम करने वाले पार्टी नेता खुद को उपेक्षित महसूस करने लगे। दल-बदलू नेताओं को भाजपा में पूरी तरजीह मिली। इसका फायदा उठाकर उन्होंने जहां आर्थिक रूप से मजबूती प्राप्त की, वही पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर अपने समर्थकों को विभिन्न पदों पर बैठाया। इससे पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं में निराशा व्याप्त होने के कारण वह धीरे-धीरे मुख्यधारा से किनारे हो गए। लंबे समय तक सत्ता का दोहन करने के कारण अन्य दलों से भाजपा में आये बहुत से नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे। उनके नाम के साथ कई तरह के विवाद जुड़ गए। ऐसे में चुनाव नजदीक आने पर जब उन्हें पार्टी में फिर से टिकट नहीं मिलने का अंदेशा हो गया तो उन्होंने अपने पद पर रहते ही भाजपा विरोधी किसी अन्य पार्टी में शामिल हो गए। इससे एक तो चुनाव के वक्त पार्टी छोड़ने से जहां भाजपा की हवा खराब हुई। वहीं, पार्टी के सामने एकाएक मजबूत प्रत्याशी खड़ा करना मुश्किल हो गया। दूसरे दलों से भाजपा में आए कई नेताओं ने तो पद पर रहते ही भाजपा को अलविदा कह कर पार्टी की किरकिरी भी कराई। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से भाजपा में आए नाना पटोले ने भाजपा टिकट पर प्रफुल्ल पटेल जैसे दिग्गज नेता को पराजित किया था। मगर तीन साल बाद ही उन्होंने भाजपा व संसद से इस्तीफा देकर कांग्रेस की सदस्यता ले ली थी। नाना पटोले के इस्तीफा देने के बाद भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मधुकर राव कुकड़े ने भाजपा प्रत्याशी हेमन्त श्रवण पटेल को हरा दिया था। उस उप चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को कांग्रेस का भी समर्थन प्राप्त था। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान दूसरी पार्टी से भाजपा में आए उत्तर पश्चिम दिल्ली में सांसद उदित राज, उत्तर प्रदेश में बहराइच के सांसद रही सावित्रीबाई फुले, आजमगढ़ से पूर्व सांसद रमाकांत यादव, हिमाचल प्रदेश के सुखराम जैसे कई बड़े नेताओं ने भाजपा छोड़कर दूसरे दलों का दामन थाम लिया था। जो कुछ वर्षों पूर्व ही दूसरी पार्टियों से भाजपा में आए थे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पूर्व मुकुल राय सहित बहुत से बड़े नेता भाजपा में शामिल हुए थे। सभी को बंगाल में भाजपा सरकार बनती दिख रही थी। इसलिए अपने लाभ के लिए भाजपा में आने वालों की बहुत बड़ी संख्या थी। मगर जैसे ही विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और ममता बनर्जी भारी बहुमत से तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी। उसके बाद भाजपा में दूसरे दलों से आए दलबदलू नेताओं ने पार्टी को छोड़ना शुरू कर दिया। सबसे पहले भाजपा के बड़े नेता व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय ने ममता बनर्जी से फिर से हाथ मिला लिया। उसके बाद केंद्र में मंत्री रहे बाबुल सुप्रियो ने मंत्री पद से हटाने से नाराज होकर भाजपा व संसद सदस्यता से त्यागपत्र देकर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। अब तक बंगाल में भाजपा के कई बड़े नेता व करीबन दस विधायक तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। इसी तरह 2017 में विधानसभा चुनाव के दौरान उत्तराखण्ड में कांग्रेस से भाजपा में आकर मंत्री बने यशपाल आर्य अपने विधायक बेटे संजीव आर्य के साथ व हरक सिंह रावत भाजपा छोड़कर फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, दारा सिंह चौहान मंत्री पद से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उनके साथ ही करीबन 15 अन्य विधायकों ने भी भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। इनके अलावा टिकट नहीं मिलने पर कई अन्य नेताओं के भी भाजपा छोड़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि भाजपा ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बड़े नेता के पार्टी छोड़ने पर उनके प्रतिद्वंदी रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस के बड़े नेता आरपीएन सिंह को भाजपा में शामिल कर लिया है। आरपीएन सिंह, स्वामी प्रसाद मौर्य के क्षेत्र पडरौना से ही पूर्व में तीन बार विधायक रह चुके हैं। वह मौर्य की कुर्मी जाति से हैं तथा पडरौना उनका परंपरागत विधानसभा क्षेत्र रहा है। पार्टी में चल रहे दलबदल के बारे में भाजपा के बड़े नेताओं का कहना है कि जिनके टिकट कटने की पूरी संभावना है, वही लोग पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में जा रहे हैं। मगर भाजपा को भी अपने अंतर्मन में झांकना होगा कि ऐन चुनाव के वक्त पार्टी के नेता पार्टी छोड़कर क्यों जाते हैं। इसके जिम्मेवार कहीं न कहीं पार्टी के ही बड़े नेता है। जो सिर्फ सरकार बनाने के लिए बिना सोचे समझे दूसरे दलों के ऐसे नेताओं को पार्टी में शामिल कर लेते हैं जिनकी भाजपा के प्रति ना तो कभी निष्ठा रही है ना ही भाजपा की विचारधारा से उनका तालमेल रहा है। पिछले सात वर्ष से अधिक समय से भाजपा की केंद्र में सरकार चल रही है। अधिकांश राज्यों में भी भाजपा व उनके सहयोगी दलों की सरकार है। ऐसे में भाजपा आलाकमान को सोचना चाहिए कि दूसरे दलों से आने वाले नेताओं को पार्टी में शामिल करने के बजाए अपनी ही पार्टी का संगठन मजबूत किया जाए।

विवेक शक्ति

जग्गी वासुदेव

कोई भी नर्क को समाप्त कर केवल स्वर्ग को नहीं रख सकता, मगर आप हर समय आनंदमय रह सकते हैं, इसलिये नहीं कि नर्क बनाने की संभावना आप के मन में घूम नहीं रही है, बल्कि अपनी विवेक शक्ति को ज्यादा मजबूत बनाकर। आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि नर्क का फैलाव आप के अंदर कभी न हो। इसके प्रति सजग रह कर आप ऐसा कर सकते हैं वरना नर्क के फैलाव की संभावना तो हर समय है ही। ये सजग रहने की योग्यता भी एक सीमा तक ही होती है। लेकिन अगर आप सारी निर्माण सामग्री को हटा दें, जो ऐसा या वैसा करने में सक्षम है, तो फिर ये बिल्कुल वैसा हो जाएगा कि आप किसी अंधेरे कमरे में बैठे हों, जहां न नीले प्रकाश की संभावना है, न ही सफेद की। लेकिन अब आप एक ऐसी दिशा में मुड़ गए हैं जहां प्रकाश का कोई महत्त्व नहीं है। प्रकाश सिर्फ उसके लिए है, जो आंख खोल कर कहीं जाना चाहता है। जिसने आंखें बंद कर ली है और किसी दूसरी ही जगह है, उसके लिए प्रकाश से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए तो प्रकाश अड़चन है। तो असत्य से सत्य की ओर जाने का मतलब किसी भौगोलिक दूरी को पार करना नहीं है। यह तो एक अंडे के बाहरी खोल की तरह है- अभी आप खोल के बाहर हैं। अगर आप अंदर की ओर मुड़ना चाहते हैं तो आप अंडे के साथ टक, टक, टक करने लगते हैं। आप को लगता है कि जब ये टूट जाएगा तो आप अंदर चले जाएंगे, पर नहीं, चूजा बाहर आएगा पूरी बात यही है। आप यहां बैठ कर अंदर जाना चाहते हैं। जब आप इसे तोड़ लेते हैं तो कोई अंदर नहीं जाता, एक पूरी तरह से नई संभावना बाहर आती है। इसीलिए, योग में जो प्रतीक चिह्न है वो सहस्त्रार है-एक हजार पंखुड़ियों वाला पुष्प, जो बाहर आ रहा है, खिल रहा है। आप जब खोल को तोड़ते हैं तो आप ने जिसकी संभावना की कभी कल्पना भी नहीं की थी, वह चीज बाहर आती है। तो अगर आप इस आवरण को तोड़ना चाहते हैं तो आप कभी भी ये काम खुद नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप खुद ही आवरण हैं। आप खुद को कैसे तोड़ पाएंगे? यह कर सकने के लिए आप के पास आवश्यक साहस नहीं है। मन भले कहे,'चलो, इसे तोड़ते हैं, एक चूजा बाहर आएगा'। पर नहीं, आप में ये हिम्मत नहीं होगी कि आप इसे खुद तोड़ सकें।

सू-दोकू नवताल -2035

		8		1	6			3
			4					2
9			5	8		1		
	4			3			2	1
6		5	7		4	3		8
2	8			6			7	
		7		5	8			4
3					2			
8			3	9		5		

सू-दोकू -2034 का हल

3	9	1	5	8	2	6	7	4
5	2	7	3	4	6	9	8	1
8	6	4	7	9	1	5	2	3
4	8	3	6	2	9	1	5	7
6	1	5	4	7	3	2	9	8
2	7	9	1	5	8	3	4	6
9	3	8	2	6	4	7	1	5
1	5	2	8	3	7	4	6	9
7	4	6	9	1	5	8	3	2

प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं। इनका क्रमवार होना आवश्यक नहीं है। आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3 X 3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें।

फिल्म वर्ग पहेली-2035

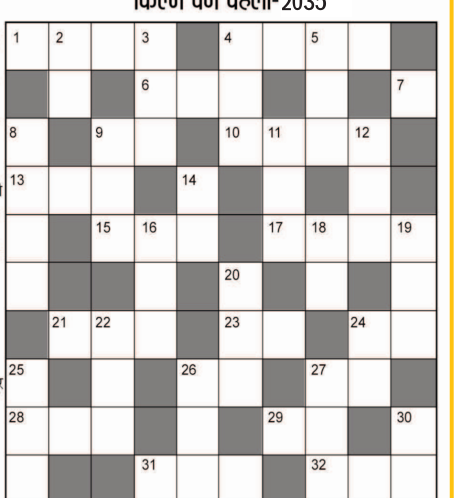

बायें से दायें:-

1. धर्मेन्द्र, राखी की 'पल पल दिल के पास' गीत वाली फिल्म-2,2
4. 'इमली का बूटा' गीत वाली दिलीपकुमार, राजकुमार, विवेक मुशरान, मनीषा की फिल्म-4
6. अक्षय, सैफ, रवीना, सोनाली की 'नहीं कही थी बात' गीत वाली फिल्म-3
7. 'आईने के सौ टुकड़े' गीत वाली जीतेंद्र, जयाप्रदा की फिल्म-1
9. लक्की अली, गौरी कार्णिक की 'खोया है तूने जो' गीत वाली फिल्म-2
10. राकेश रोशन, योगिता बाली की 'लो मेरा प्यार लेलो' गीत वाली फिल्म-4
13. 'तुम्ही रहनुमा हो' गीत वाली अनिल धवन, राधा सलूजा की फिल्म-3
15. सुनीलदत्त, मीनाकुमारी की 'रंग और नूर की' गीत वाली फिल्म-3
17. 'ए बी सी डी छोड़ो' गीत वाली धर्मेन्द्र, हेंमा मालिनी की फिल्म-2,2
21. राजेंद्रकुमार, वैजयंतीमाला की 'हमसे तो अच्छी तेरी' गीत वाली फिल्म-3
23. 'कोई देख रहा रहा' गीत वाली सनी देओल, सुष्मिता सेन की फिल्म-2
24. सुनील शेट्टी, सोमी अली की 'आ जा जाने जां' गीत वाली फिल्म-2
26. 'मैं तेरा मजनूं' गीत वाली गोविंदा, सोनाली, शिल्पा शेट्टी की फिल्म-2
27. शाहरूख, चंद्रचूड़, ऐश्वर्या की 'मेरे खयालों की' गीत वाली फिल्म-2
28. 'अपने दिल में जगह' गीत वाली अनिल धवन, नीतूसिंह की फिल्म-3
29. फरदीनखान, करीना कपूर की 'तेरे बिना तेरे बिना' गीत वाली फिल्म-2
31. 'मेरे ख्वाबों का' गीत वाली अजय देवगन, अभिषेक, बिपाशा की फिल्म-3
32. अनिलकपूर, श्रीदेवी, रवीना की 'मैं राजू दीवाना' गीत वाली फिल्म-3

ऊपर से नीचे:-

2. सनी देओल, सुनील, शिल्पा की 'कोई परी आती नही' गीत वाली फिल्म-2
3. 'ओ नचलै नचलै' गीत वाली सनी, सोहेल, सुनील, जॉन की फिल्म-3
4. राजेश खन्ना, टीना, पद्मिनी की फिल्म-3
5. 'मैं निकला गड्डी लेके' गीत वाली फिल्म-3
8. संजयदत्त, गोविंदा, दिव्या, ममता की 'दिल तो खोया है' गीत वाली फिल्म-4
9. 'गोरे गोरे मुखड़े पे' गीत वाली अजय, अक्षय, करिश्मा, नगमा की फिल्म-3
11. शशिकपूर, शबाना आजमी की फिल्म-3
12. 'हाथी मेरे साथी' की नायिका?-3
14. 'तुमको कितना है' गीत वाली सनी, सुनील, सेलिना जेटली की फिल्म-2
16 संजयकपूर, शिल्पा शेट्टी की 'टक टका टक' गीत वाली फिल्म-3
18. 'चांदनी रातें प्यार की बातें गीत वाली देवआनंद, गीताबाली की फिल्म-2
19. शशिकपूर, जीतेंद्र, रेखा की 'प्यार करना नहीं आया' गीत वाली फिल्म-3
20. 'यशोदा का नंदलाला' गीत वाली जयाप्रदा, जीतेंद्र, विनोद की फिल्म-3
22. 'एक बेचारा प्यार का मारा' गीत वाली फिल्म-3
24. 'जो बीच बजरिया' गीत वाली अब्बास, शर्बाणी मुखर्जी की फिल्म-2
25. विश्वजीत, वहीदा रहमान की फिल्म-3
26. 'आज पुरानी राहों से' गीत वाली फिल्म-3
27. देवआनंद, हेमा मालिनी की फिल्म-3
30. 'आज सरे महफिल' गीत वाली फिल्म-2

फिल्म वर्ग पहेली-2034

ता	रे	ज	मी	न	प	र		घा	त
ल		मी		वी		क्ष	त्रि	य	
	जा	न	शी	न		क		ल	व
दि	ल			नि	शा		गै		च
ल्ल		गो		श्च		अ	र	मा	न
गी	त		स	ल	मा	न		या	
	नू	त	न			जा	न		इं
रो	जा		म	न		न	सी	ह	त
टी		खौ		का	श		ब		का
	आ	फ	ता	ब		डी		तु	म

वित्तमंत्री सीतारमण ने संसद में पेश किया आम बजट-2022

आम आदमी को झटका, लेकिन 60 लाख नई नौकरिया

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूर्णकालिक वित्त मंत्री के रूप में अपना चौथा और मोदी सरकार 10वां आम बजट पेश किया। इस बार के बजट में आम आदमी की उम्मीदों को एक बार फिर से झटका लगा है। दरअसल, इस बार भी सरकार की ओर से आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि, कुछ मामलों में आम आदमी को राहत देने की घोषणाएं भी की गई हैं। जैसे कि आयकर रिटर्न फाइल करने में हुई गड़बड़ी को सुधारने के लिए दो साल का समय दिया गया है। देश में 80 लाख नए घर बनाए जाएंगे और 60 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा आरबीआई की ओर से इस साल डिजिटल करेंसी लॉन्च किए जाने का एलान किया गया है।

60 लाख रोजगार पैदा होंगे

जैसा कि बजट पेश होने से पहले उम्मीद की जा रही थी कि इस बार सरकार का जोर रोजगार मुहैया कराने और बढ़ती बेरोजगारी से निपटने पर होगा। तो इस मामले में वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी कोशिश 60 लाख नए रोजगार का सृजन करने की होगी।

एमएसपी सीधे किसानों के खाते में

किसानों को राहत देते हुए वित्त मंत्री ने एलान किया कि अब 2.37 लाख करोड़ रुपये की एमएसपी सीधे किसानों के खाते में भेजी जाएगी। इसके साथ ही किसानों को डिजिटल सर्विस मिलेगी, जिसमें दस्तावेज, खाद, बीज, दवाई से संबंधित सेवाएं शामिल हैं।

क्रिप्टोकरेंसी से आय पर टैक्स

केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने अपने बजट भाषण में आभासी मुद्रा या क्रिप्टोकरेंसी को लेकर बड़ा एलान किया है। उन्होंने कहा कि अब क्रिप्टोकरेंसी के जरिए होने वाली आय पर 30 फीसदी का टैक्स चुकाना होगा।

डाकघर में एटीएम सुविधा

बजट 2022 के प्रमुख एलानों की फेहरिस्त में डाकघर डिजिटल किए जाने की भी घोषणा की गई। वित्त मंत्री के अनुसार, देश के 1.5 लाख डाकघर अब कोर बैंकिंग से जुड़ेंगे। डाकघरों में एटीएम सुविधा दी जाएगी, पोस्ट ऑफिस में डिजिटल सुविधाएं मिलेंगी।

आईटीआर में सुधार के लिए 2 साल

अपनी बजट घोषणाओं के क्रम में हालांकि, वित्त मंत्री ने आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन आयकर रिटर्न फाइल करने में हुई गड़बड़ी को सुधारने के लिए दो साल का समय दिया गया है। इससे करदाताओं को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी।

80 लाख नए घर बनेंगे

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देशभर में 80 लाख नए घर बनाए जाने का बड़ा एलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से किया गया। उन्होंने कहा कि इसके लिए वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में 48 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे।

400 नई वंदेभारत ट्रेनें चलेंगी

वित्त मंत्री ने एलान किया कि 400 नई पीढ़ी की वंदेभारत ट्रेनें अगले 3 साल के दौरान चलाई जाएंगी। 100 प्रधानमंत्री गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल भी इस दौरान डेवलप किए जाएंगे। मेट्रो सिस्टम को विकसित करने के लिए नए तरीके अपनाए जाएंगे।

2022 में 5जी की शुरुआत

सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान देश में 5त्न और ऑप्टिकल फाइबर सेवाओं को लेकर बड़ी घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि साल 2022-23 में 5त्न मोबाइल सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। इसके बाद से निजी दूरसंचार कंपनियां देश में 5त्न सेवाओं की शुरुआत कर सकेंगी।

आरबीआई लाएगी डिजिटल रुपया

आरबीआई की डिजिटल मुद्रा का इंतजार खत्म होने वाला है। दरअसल, वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि इस साल भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अपनी ब्लॉकचैन और नई तकनीक पर आधारित रुपया लॉन्च करेगी।

ई-पासपोर्ट की मिलेगी सुविधा

वित्त मंत्री ने बजट 2022-23 में कई बड़े एलान करने के साथ ही ई-पासपोर्ट को लेकर भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष में ई-पासपोर्ट जारी किए जाएंगे, जिनमें चिप लगी होगी। इनके जरिए विदेश जाने वाले लोगों को सहूलियत होगी।

एनपीएस योजना में बदलाव

वित्त मंत्री ने नेशनल पेंशन स्कीम- एनपीएस (हृक्क) को लेकर बड़ा एलान किया। अब एनपीएस में नियोक्ता का अंशदान बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार के कर्मचारी अब एनपीएस में 14 फीसदी अंशदान दे सकेंगे।

पीएम गति शक्ति का मास्टर प्लान तैयार

प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का मास्टर प्लान तैयार है। इसके तहत नेशनल हाईवे नेटवर्क 25 हजार किमी तक बढ़ाया जाएगा। इस मिशन के लिए 20 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बता दें कि इस योजना का शुभारंभ 13 अक्तूबर 2021 को पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था।

निवेश बढ़ाने के लिए 7.55 लाख करोड़

पूंजी निवेश से रोजगार बढ़ाने में बड़े उद्योगों और एमएसएमई दोनों से मदद मिलती है। वित्त मंत्री ने कहा कि निजी निवेशकों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इसके लिए केंद्रीय बजट में 5.54 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7.55 लाख करोड़ रुपये करने का प्रावधान किया गया है।

एमएसएमई के लिए 6 हजार करोड़

बजट में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने के लिए नई योजनाएं शुरू करने का वादा किया गया। इसके लिए 5 साल में 6000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। उदयम, ई-श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल आपस में जुड़ेंगे। इससे संभावनाएं और बढ़ेंगी।

ऑर्गेनिक खेती को मिलेगा बढ़ावा

कृषि क्षेत्र को लेकर एक और बड़ा एलान किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि गंगा के किनारों के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाली जमीन पर ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा खेती की जमीन के दस्तावेजों का डिजिटलीकरण होगा।

1486 अनुपयोगी कानून होंगे खत्म

सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान कहा कि देश में लागू 1486 अनुपयोगी कानूनों को खत्म करने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने एलान किया कि अब सेस की जगह नया कानून लाया जाएगा।

रक्षा क्षेत्र में रिसर्च के लिए 25त्न बजट

वित्त मंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए अनुसंधान और विकास बजट का 68 फीसदी हिस्सा मेक इन इंडिया के लिए निर्धारित किया गया है। रक्षा में अनुसंधान के लिए 25 फीसदी बजट और उत्पादन का आयात कम करने की घोषणा हुई।

पीएम ई-विद्या प्रोग्राम का दायरा बढ़ा

महामारी के दौरान स्कूल बंद रहने से गांव के बच्चों को दो साल शिक्षा से वंचित रहना पड़ा। पीएम ई-विद्या के तहत ऐसे बच्चों के लिए एक क्लास-एक टीवी चैनल प्रोग्राम के तहत अब चैनल 12 से बढ़ाकर 200 कर दिए जाएंगे। ये चैनल क्षेत्रीय भाषाओं में होंगे।

डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना

वित्त मंत्री ने कहा कि अब कक्षा 1 से 12वीं तक की पढ़ाई क्षेत्रीय भाषा में होगी। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तकनीक की मदद ली जाएगी। एक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी।

कॉर्पोरेट टैक्स 15 फीसदी किया

बजट 2022 में केंद्र सरकार द्वारा सहकारी संस्थाओं का टैक्स घटाकर 15 फीसदी करने की घोषणा की गई। वित्त मंत्री ने एलान किया कि अब कॉरपोरेट टैक्स में बदलाव करते हुए इसे 18 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी किया गया है।

दो लाख आंगनबाड़ी अपग्रेड होंगी

बजट 2022 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा आंगनबाड़ी को लेकर भी बड़ा एलान किया गया है। उन्होंने बजट भाषण के दौरान कहा कि 2 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा। इससे बड़ी राहत मिलेगी।

सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड होंगे जारी

क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जारी किए जाएंगे। इससे मिलने वाली रकम को ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगाया जाएगा, जो कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में मददगार होंगे। सेमी कंडक्टर निर्माण के लिए इंडस्ट्री डेवलप की जाएगी। इससे निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा।

पीएम मोदी बोले, ये 100 साल के विश्वास का बजट है, सभी वर्गों को मिलेगा फायदा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस बजट का सबने स्वागत किया है, बजट से सभी वर्गों को फायदा मिलेगा, ये 100 साल के विश्वास का बजट है। उन्होंने कहा कि इस बजट से अर्थव्यवस्ता को मजबूती मिलेगी। यह आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देगा। पीएम मोदी कल सुबह बजट पर चर्चा करेंगे। पीएम ने कहा कि बजट में भारत के कोटि-कोटि जनों की आस्था, मां गंगा की सफाई के साथ-साथ किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन पांच राज्यों में गंगा किनारे, नैचुरल फॉर्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ घंटों से देख रहा हूं, जिस प्रकार से इस बजट का हर क्षेत्र में स्वागत हुआ है, सामान्य मानव की जो सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है, उसने जनता-जनार्दन की सेवा का हमारा उत्साह अनेक गुना बढ़ा दिया है। ये बजट मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इनवेस्टमेंट, मोर ग्रोथ, और मोर जॉब्स की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। ये बजट 100 साल की भयंकर आपदा के बीच, विकास का नया विश्वास लेकर आया है। ये बजट, अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए, अनेक नए अवसर बनाएगा।

नए भारत की नींव रखेगा बजट : शाह

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार का वर्ष 2022-23 के लिए पेश बजट कोरोना महामारी के बाद के विश्व में देश को आत्मनिर्भर बनाने और आजादी के 100वें वर्ष के नए भारत की नींव रखेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को लोकसभा में आम बजट पेश किए जाने के बाद शाह ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया करते हुए सिलसिलेवार ट्वीट में यह बात कही। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार द्वारा लाया गया ये बजट, एक दूरदर्शी बजट है, जो भारत की अर्थव्यवस्था का स्केल बदलने वाला बजट साबित होगा। ये बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने के साथ स्वतंत्रता के 100वें वर्ष के नए भारत की नींव डालेगा। इसके लिए नरेन्द्र मोदी जी और निर्मला सीतारमण जी का अभिनंदन करता हूं। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का यह बजट कोरोना के बाद वैश्विक आर्थिक जगत में उत्पन्न हुए अवसरों का दोहन करके प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि बजट का आकार बढ़ाकर 39.45 लाख करोड़ करना कोरोनाकाल में भी भारत की तेज़ी से बढती अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। वित्तीय घाटे का लक्ष्य 6.9त्न से घटाकर 6.4त्न करना बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत वित्तीय घाटे को 4त्न से नीचे लाने में सफल होगा।

राहुल ने आम बजट को जीरो सम बजट करार दिया, बोले- सरकार ने युवाओं, किसानों को कोई राहत नहीं दी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आम बजट पेश किया। जिसको लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने निशाना साधा और इसे जीरो सम बजट करार दिया। उन्होंने कहा कि इस बजट में वेतनभोगी, मध्यम वर्ग, गरीब और वंचितों, युवा, किसान और एमएसएमई के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि मोदी सरकार के बजट में कुछ नहीं है। मध्य वर्ग, वेतनभोगी वर्ग, गरीब और वंचित वर्ग, युवाओं, किसानों और एमएसएमई के लिए कुछ नहीं है। आपको बता दें कि सरकार ने इस बार इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। जिसको कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि भारत का वेतनभोगी वर्ग एवं मध्य वर्ग महामारी, वेतन में चौतरफा कटौती और कमरतोड़ महंगाई के इस दौर में राहत की उम्मीद कर रहा था।

केंद्रीय बजट आम आदमी को निराश करने वाला और अमीरों का बजट है-कांग्रेस

केंद्रीय बजट में आमजन और मध्यमवर्ग को निराशा ही हाथ लगी है।सरकार ने आयकर सीमा में कोई भी बढ़ौतरी नहीं की है जिसके चलते मध्यमवर्ग को निराशा ही हाथ लगी है। यह प्रतिक्रिया हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता दीपक शर्मा ने आज मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि कोविड संकटकाल को देखते हुए सरकार गरीब,मध्यमवर्ग सहित किसानों और छोटे व्यापारियों को विशेष छूट देकर राहत देगी लेकिन मोदी सरकार का यह बजट बड़े घरानों को तो फायदा पहुंचाता नज़र आ रहा है लेकिन आमजन की अनदेखी हुई है।

वित्त मंत्री के एलान में क्या हुआ महंगा और क्या हुआ सस्ता

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2022-23 का आम बजट लोकसभा में पेश किया। इस बजट में युवाओं को 60 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया है। वहीं एक साल के अंदर गरीबों के लिए पूरे देश में 80 लाख किफायती मकान बनाए जाएंगे। बजट में बहुत सी चीजें महंगी की गई हैं। वहीं, कुछ चीजों को सस्ता किया जा रहा है। जानिए बजट में आम आदमी को कहां-कहां मिली राहत और कहां जेब हुई ढीली...

क्या महंगा और क्या सस्ता

- ✔ कपड़ा, चमड़े का सामान होगा सस्ता
- ✔ मोबाइल फोन और चार्जर सस्ता होगा
- ✔ हीरे की ज्वेलरी सस्ती होगी
- ✔ खेती का सामान सस्ता होगा
- ✔ पॉलिस हीरे पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई
- ✔ विदेशी मशीनें सस्ती होंगी
- ✔ इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ते होंगे
- ✔ जूते-चप्पल सस्ते होंगे
- ✔ आर्टिफिशियल गहने महंगे होंगे
- ✔ छाते महंगे होंगे
- ✔ स्टील सस्ती होगी
- ✔ बटन, पैकेजिंग बॉक्स सस्ता होगा
- ✔ बिना ब्लेंडिंग वाला फ्यूल महंगा होगा
- ✔ कैपिटल गुड्स महंगे होंगे

बजट में निर्मला सीतारमण ने गति शक्ति सहित सरकार की 4 बड़ी प्राथमिकताओं की रूपरेखा तैयार की

नयी दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि टीकाकरण का दायरा बढ़ाने से आर्थिक पुनरुद्धार में मदद मिली है। सीतारमण ने लोकसभा में बजट 2022-23 पेश करते हुए कहा कि देश में अभी कोरोना वायरस के ओमीक्रोन स्वरूप का प्रकोप है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को अपने केंद्रीय बजट 2022 के भाषण में सरकार की चार बड़ी प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। इन चार बड़ी प्राथमिकताओं में नरेंद्र मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना पीएम गति शक्ति शामिल है।

एफएम सीतारमण ने कहा इस समानांतर ट्रैक पर आगे बढ़ते हुए, हम निम्नलिखित चार प्राथमिकताएं रखते हैं - पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता वृद्धि और निवेश, सूर्योदय के अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई।

अक्टूबर 2021 में शुरू की गई मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समन्वित योजना और निष्पादन के उद्देश्य से एक पहल है। इसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना है। गति शक्ति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो एकीकृत योजना और कार्यान्वयन के लिए रेलवे और रोडवेज सहित 16 मंत्रालयों की विकास परियोजनाओं को एक साथ लाता है। लॉन्च होने पर, गति शक्ति योजना ने 2019 में घोषित 110 लाख करोड़ रुपये की राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन को शामिल कर लिया।

एफएम सीतारमण ने मंगलवार को वित्तीय वर्ष के लिए केंद्रीय बजट 2022 पेश किया जो 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है। पिछले वित्त वर्ष में 7.3 प्रतिशत के संकुचन के बाद, 31 मार्च को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष में एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का 9.2 प्रतिशत विस्तार होने का अनुमान है। बजट प्रस्तुति के लिए चरण आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा निर्धारित किया गया था, जिसमें कहा गया था कि सरकार के पास अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए और अधिक करने के लिए राजकोषीय स्थान है, जो कि 2022-23 के वित्तीय वर्ष में 8 प्रतिशत से 8.5 प्रतिशत की स्वस्थ विकास दर से बढ़ने का अनुमान है।

भाजपा ने बजट को बताया दूरदर्शी, कहा- यह भारत की अर्थव्यवस्था का स्केल बदलने वाला साबित होगा

नयी दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2022 का बजट पेश किया। बजट को भविष्य का बजट बताया जा रहा है। इन सब के बीच केंद्रीय मंत्रियों ने बजट की जमकर सराहना की है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा लाया गया ये बजट, एक दूरदर्शी बजट है, जो भारत की अर्थव्यवस्था का स्केल बदलने वाला बजट साबित होगा। ये बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने के साथ स्वतंत्रता के 100वें वर्ष के नए भारत की नींव डालेगा। इसके लिए नरेंद्र मोदी और निर्मला सीतारमण का अभिनंदन करता हूँ। उन्होंने कहा कि बजट का आकार बढ़ाकर 39.45 लाख करोड़ करना, कोरोनाकाल में भी भारत की तेज़ी से बढती अर्थव्यवस्था को दर्शाता है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह एक ऐसा बजट है जो 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देगा, मांग को बढ़ावा देगा और एक मजबूत, समृद्ध और आत्मविश्वास से भरे भारत के लिए क्षमता का निर्माण करेगा। बजट आत्मानिर्भर भारत तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास और जन सुधारों के लिए दृष्टिकोण पर सरकार के फोकस को रेखांकित करता है। यह एक विकासोन्मुखी बजट है जो न्यू इंडिया की ऊर्जा का उपयोग करने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि भूमि सुधारों का डिजिटलीकरण भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदल देगा और यह किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए नए अवसर पैदा करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। मैं इस साल की बजट घोषणाओं का तहे दिल से स्वागत करता हूं।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देशभर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, साथ ही पीपीपी मॉडल के तहत स्कीम लाई जाएंगी, जिससे किसानों तक डिजिटल और हाईटेक तकनीक पहुंचाई जाएगी जिससे किसानों को फायदा होगा। किसान, महिला और युथ पर फोकस रहे इस वर्ष के बजट में पीएम गति शक्ति के जरिए विकास पर जोर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि ये बहुत समावेशी बजट है, ये बजट गरीबों, गांव, पूर्वोत्तर के लिए है। इस बजट में वित्तीय क्षेत्र में काफी रिफॉर्म लाए गए हैं। जिस तरह से अर्थव्यवस्था में रिकवरी हुई है, उस तरह से ये बहुत अच्छा बजट है।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं, ये बजट समृद्ध, शक्तिशाली और विकसित भारत के निर्माण का बजट है। अधोसंरचना विकास के लिए 35त्न से अधिक राशि बजट में बढ़ाई गई है इससे अधोसंरचना विकास के साथ-साथ रोजगार के अवसर सृजित होंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि सेवा, कृषि और चिकित्सा के क्षेत्र हमारी प्राचीन अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इन्हें नए सिरे से इस बजट में परिभाषित किया गया है। आने वाली नई चुनौतियों के लिए इस बजट में समाधान दिया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस कालखंड का यह अमृत बजट है, आज का बजट आम आदमी की आकांक्षाओं के अनुरूप है। ये बजट सबका साथ, सबका विकास के मूलमंत्र पर आधारित है, इसमें सभी वर्ग के लोगों का ध्यान रखा गया है।

रुपया गिरावट के साथ बंद

मुंबई । अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मंगलवार को भारतीय रुपया नीचे आया है। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 17 पैसे की गिरावट के साथ ही 74.82 (अस्थायी) प्रति डॉलर पर बंद हुआ। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 74.53 के स्तर पर खुला और दिन में कारोबार के दौरान इसने 74.41 के ऊपरी स्तर और 74.87 के निचले स्तर को देखा। कारोबार के अंत में रुपया अमेरिकी मुद्रा के मुकाबले 17 पैसे की गिरावट के साथ 74.82 (अस्थायी) पर बंद हुआ। वहीं पिछला बंद भाव 74.65 रुपये प्रति डॉलर था। इसके अलावा छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की स्थिति को दिखाने वाला डॉलर सूचकांक 0.19 पफीसदी नीचे आकर 96.35 रह गया।

विमान ईंधन के कीमतों में 8.5 की रिकॉर्ड उछाल

नई दिल्ली । देशभर में विमान ईंधन (एटीएफ) के दामों में रिकॉर्ड उछाल देखी गई हैं। विमान ईंधन की कीमतों में 8.5 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी की गई है। इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच एटीएफ के दाम बढ़ाए गए हैं। जहां जेट ईंधन के दाम एक महीने में तीसरी बार बढ़ाए गए हैं। वहीं पेट्रोल और डीजल कीमतों में रिकॉर्ड 88 दिन से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में एटीएफ का दाम 6,743.25 रुपये प्रति किलोलीटर की वृद्धि के साथ 86,038.16 रुपए प्रति किलोलीटर पर पहुंच गया है। यह एटीएफ कीमतों का रिकॉर्ड स्तर है। इससे पहले नवंबर, 2021 के मध्य में एटीएफ का दाम 80,835.04 रुपये प्रति किलोलीटर की ऊंचाई पर पहुंचा

महिंद्रा वाहनों की कुल बिक्री में जनवरी में 20 फीसदी इजाफा

नई दिल्ली । मशहूर वाहन निर्माण करने वाली कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा (एमएंडएम) की कुल बिक्री जनवरी, 2022 में 19.55 प्रतिशत बढ़कर 46,804 इकाई पर पहुंच गई। महिंद्रा ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि एक साल पहले इसी महीने में उसने 39,149 गाड़ियों की बिक्री की थी। मुंबई स्थित वाहन विनिर्माता कंपनी ने कहा कि जनवरी, 2022 के दौरान उसने घरेलू बाजार में 19,964 इकाइयां बेचीं जबकि एक साल पहले इसी महीने में उसने 20,634 इकाइयों की बिक्री की थी। इसके अलावा कंपनी के वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री जनवरी 2022 में बढ़कर 23,979 इकाई पर पहुंच है। एक साल पहले इसी महीने में कंपनी ने इस श्रेणी में 16,229 इकाइयां बेचीं थी। कंपनी ने कहा कि पिछले महीने उसका निर्यात 2,861 इकाई रहा, जो पिछले साल इसी महीने में 2,286 इकाई था।

महामारी के उन्मूलन से चक्र निवेश को मिलेगी गति : सीईए

नई दिल्ली । देश के नवनियुक्त मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि कोविड-19 महामारी के उन्मूलन से चक्र निवेश को गति मिलेगी और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि टीकाकरण अभियान से इस दिशा में सफलता मिलने की उम्मीद है। उन्होंने दिन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश की गई समीक्षा पर मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार ने निम्न आय वर्ग को समर्थन देने के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जाहिर है कि विश्वास बहाली में वक्त लगेगा, क्योंकि उपभोक्ता खर्च में मंदी की वजह सिर्फ आय में कमी नहीं है, बल्कि महामारी और स्वास्थ्य संबंधी अनिश्चितता के कारण भी ऐसा हो रहा है। नागेश्वरन ने कहा, 'इसलिए एक बार जब महामारी के बादल छंट जाएंगे, और कई संपर्क सेवाएं महामारी से पहले के स्तर पर वापस आ जाएंगी, तो आय में बढ़ोतरी और रोजगार सृजन को भी बढ़ावा मिलेगा।' उन्होंने कहा कि निर्माण क्षेत्र में सुधार होने लगा है और यह देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाले क्षेत्रों में है।

पीएम मोदी ने आम बजट को सकारात्मक बताया, कहा- 'यह युवाओं का भविष्य करेगा उज्ज्वल'

नई दिल्ली ।

देश की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के आम बजट भाषण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए बजट को शानदार कहते हुए कई घोषणाओं का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि यह बजट आम आदमी के लिए कई अवसर पैदा करेगा। यह बजट अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रोथ और संभावनाओं से भरा है। इस बजट के जरिए ग्रीन जॉब्स का नया सेक्टर खुला है। इससे देश के युवाओं का भविष्य उज्ज्वल होगा। इस बजट का हर क्षेत्र में स्वागत हुआ है और लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है। इससे जनता की सेवा करने का उत्साह भी बढ़ा है। लोगों के जीवन में वंदे भारत ट्रेन, डिजिटल करंसी, किसानों के लिए ड्रोन, नेशनल हेल्थ के लिए डिजिटल ईकोसिस्टम जैसी घोषणाओं से सबको फायदा होगा। पीएम मोदी ने इस बजट को गरीबों का कल्याण करने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि हर गरीब को पक्का घर मिले, हर नल में जल आए, उनके पास शौचालय हो और गैस की व्यवस्था हो। इन सभी पर विशेष ध्यान देते हुए यह बजट बनाया है। साथ ही आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी जोर दिया है। हिमालय के पूरे पट्टे पर भी जीवन आसान बनाने और वहां से पलायन रोकने को ध्यान में रखते हुए भी नई घोषणाएं की गई हैं। हिमाचल और जम्मू-कश्मीर जैसे क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए पर्वतमाला योजना की शुरुआत की गई है। इससे पहाड़ों पर ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इससे सीमा के गांवों को बड़ी ताकत मिलेगी। गंगा की सफाई के साथ-साथ किसानों के कल्याण के लिए उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड जैसे राज्यों में गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे गंगा को कैमिकल मुक्त करने में मदद मिलेगी। बजट से कृषि लाभप्रद होगी और विशेष अवसर मिलेंगे। इससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी।

एमएसपी के जरिए किसानों के खाते में सवा दो लाख करोड़ से भी ज्यादा सीधे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। एमएसएमई की मदद और सुरक्षा के लिए कई फैसले लिए गए थे, इस बजट के जरिए एमएसएमई के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया गया है। पीएम ने इसे पीपल फ्रेंडली बजट कहा और निर्मला सीतारमण समेत पूरी टीम को बधाई दी।

जनवरी में मारुति की थोक बिक्री में आई चार फीसदी की गिरावट

नई दिल्ली । देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) की थोक बिक्री जनवरी, 2022 में 3.96 प्रतिशत घटकर 1,54,379 इकाई रही। मारुति ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि जनवरी, 2021 में कंपनी ने 1,60,752 वाहन बेचे थे। इसके अलावा कंपनी की घरेलू बिक्री पिछले महीने आठ प्रतिशत घटकर 1,36,442 इकाई रही, जो एक साल पहले के इसी महीने में 1,48,307 इकाई रही थी। मारुति ने कहा, 'इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की कमी का उन वाहनों के उत्पादन पर मामूली प्रभाव पड़ा जो मुख्य रूप से घरेलू बाजार में बेचे जाते हैं। हम इस प्रभाव को कम करने के लिए हर संभव कदम उठा रहे है।'

साल के पहले माह में रिकार्ड कर संग्रह : जनवरी में किया गया 1.38 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन

नई दिल्ली ।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारामण संसद में आज बजट पेश करने जा रही हैं। बजट से पहले देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे संकेत मिल रहे हैं। पिछले माह वस्तु और सेवा कर का रिकॉर्ड संग्रह हुआ है। जनवरी माह में 1.38 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन किया गया। पिछले साल के जनवरी माह के मुकाबले यह कलेक्शन 15 फीसदी ज्यादा है। सरकार को भरोसा है कि आने वाले दिनों में भी जीएसटी कलेक्शन में तेजी का यह दौर बना रहेगा। सरकार ने नए साल में 8.5 फीसदी की आर्थिक ग्रोथ का अनुमान लगाया है। उल्लेखनीय है कि यह लगातार चौथा महीना है, जब जीएसटी का कलेक्शन 1.30 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है। पिछले साल अप्रैल में अब तक सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन 1।39 लाख करोड़ रुपए हुआ था। वित्त मंत्रालय के अनुसार दिसंबर, 2021 में कुल 6.7 करोड़ ई-वे बिल तैयार किए गए थे। यह आंकड़ा नवंबर माह के मुकाबले 14 फीसदी अधिक था। नवंबर में कुल 5.8 करोड़ ई-वे बिल ही तैयार हुए थे। जनवरी में जीएसटी के कलेक्शन में 24,674 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी सीजीएसटी की है। स्टेट जीएसटी के तौर पर सरकार को 32,016 करोड़ रुपए मिले हैं। आईजीएसटी के तौर पर कुल 72,030 करोड़ रुपए हासिल हुए। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जनवरी 2022 में 18,000 करोड़ रुपए का जीएसटी मुआवजा दिया था। जनवरी 2022 के महीने के लिए राजस्व पिछले साल के इसी महीने में जीएसटी राजस्व से 15 फीसदी अधिक और जनवरी 2020 में जीएसटी राजस्व से 25 फीसदी अधिक है।

बजट के बाद हुई खरीददारी से उछला शेयर बाजार

सेंसेक्स 848 अंक , निफ्टी 237 अंक ऊपर आया

मुंबई ।

मुम्बई शेयर बाजार मंगलवार को बढ़त के साथ बंद हुआ। सप्ताह के दूसरे ही कारोबारी दिन बाजार में यह तेजी आम बजट में बुनियादी ढांचे पर जोर देने के साथ ही धातु और पूंजीगत सामान कंपनियों के शेयरों में भारी खरीदारी के अलावा दुनिया भर के बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों से आई है। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सूचकांक 59,032.20 की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद 848.40 अंक करीब 1.46 फीसदी बढ़कर 58,862.57 पर बंद हुआ। वहीं इसी प्रकार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 237 अंक तकरीबन 1.37 फीसदी ऊपर आकर 17,576.85 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के शेयरों में सबसे अधिक 7.57 फीसदी की बढ़त टाटा स्टील के शेयरों में रही। इसके अलावा सन फार्मा, इंडसइंड बैंक, एलएंडटी, अल्ट्राटेक सीमेंट, आईटीसी और एचसीएल टेक के शेयर भी ऊपर आये हैं। वहीं दूसरी ओर महिंद्रा एंड महिंद्रा, पावरग्रिड, एसबीआई, भारती एयरटेल, एनटीपीसी, मारुति और रिलायंस के शेयरों को नुकसान हुआ है। इससे पहले सुबह बाजार बढ़त के साथ खुला था। शुरुआती कारोबार में ही सेंसेक्स 600 अंक से अधिक बढ़ा जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (निफ्टी) में 159 अंक की बढ़त आई थी। सेंसेक्स में सबसे अधिक 2.45 फीसदी की बढ़त इंडसइंड बैंक में हुई। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी ट्विन्स, सन फार्मा, इंफोसिस, कोटक बैंक और बजाज फिनसर्व के शेयर भी ऊपर आये हैं।

वहीं दूसरी ओर आईटीसी और पॉवरग्रिड के शेयर नुकसान के साथ ही लाल निशान पर थे। इससे पहले गत सत्र में सेंसेक्स 813.94 अंक करीब 1.42 फीसदी की बढ़त के साथ ही 58,014.17 अंक जबकि निफ्टी 237.90 अंक बढ़कर 17,339.85 अंक के स्तर पर बंद हुआ।

अंबानी की नेटवर्थ 63 करोड़ डॉलर बढ़ी, अडानी की में 9.16 अरब डॉलर की उछाल

नई दिल्ली।

एशिया के धनाढ्यों में शुमार मुकेश अंबानी ने बजट से एक दिन पहले 2.51 अरब डॉलर यानी करीब 18,717 करोड़ रुपए की कमाई की। देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में सोमवार को 2.18 फीसदी की तेजी आई। इससे अंबानी की नेटवर्थ में तेजी आई। ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स के मुताबिक अंबानी 90.6 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 11वें नंबर पर बने हुए हैं। जहां तक इस साल कमाई का मामला है तो इसमें अडानी नंबर वन हैं। ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स के मुताबिक इस साल अडानी की नेटवर्थ में 9.16 अरब डॉलर की उछाल आई है जबकि अंबानी की नेटवर्थ 63 करोड़ डॉलर बढ़ी है। दुनिया के टॉप 10 अमीरों में इस साल केवल वॉरेन बफे की नेटवर्थ 4.47 अरब डॉलर बढ़ी है। बाकी सभी की नेटवर्थ में गिरावट आई है। दुनिया के सबसे बड़े रईस एलन मस्क की नेटवर्थ में सबसे ज्यादा 28.6 अरब डॉलर की गिरावट आई है। दुनिया की सबसे मूल्यवान ऑटो कंपनी टेस्ला के सीईओ एलन मस्क की नेटवर्थ में सोमवार को 21.4 अरब डॉलर की तेजी आई। वह 242 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ टॉप पर हैं। ऐमजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस 175 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। फ्रांसीसी बिजनसमैन और दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी गुड्स कंपनी के चेयरमैन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव बर्नार्ड आरनॉल्ट (167 अरब डॉलर) इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स (130 अरब डॉलर) चौथे नंबर पर बने हुए हैं।

सोमवार को अंबानी की नेटवर्थ में आई उछाल से उनके और गौतम अडानी के बीच फासला बढ़ गया है। ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स के मुताबिक अडानी की नेटवर्थ में सोमवार को 5.68 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ और वह 85.7 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ अमीरों की लिस्ट में अंबानी से एक स्थान नीचे 12वें नंबर पर हैं। एशिया में अंबानी पहले और अडानी दूसरे नंबर पर हैं। दोनों की नेटवर्थ में अब 4.9 अरब डॉलर का फासला आ चुका है। अमेरिकी कम्प्यूटर साइंटिस्ट और इंटरनेट उद्यमी लैरी पेज 121 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ पांचवें नंबर पर हैं। अमेरिकन मीडिया के दिग्गज और फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग 117 अरब डॉलर की वेल्थ के साथ छठे नंबर पर हैं। गूगल के को-फाउंडर सर्गेई ब्रिन 116 अरब डॉलर के साथ सातवें, जाने माने निवेशक वॉरेन बफे 113 अरब डॉलर के साथ आठवें, अमेरिकी बिजनसमैन स्टीव बाल्मर 111 अरब डॉलर के साथ नौवें और लैरी एलिसन 100 अरब डॉलर के साथ दसवें स्थान पर हैं।

फ्यूचर समूह की फर्मों की याचिकाओं पर शीर्ष कोर्ट सुनाएगा फैसला

नई दिल्ली । देश के सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को फ्यूचर समूह की फर्मों द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर फैसला सुनाएगा, जिसमें अदालत ने सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (एसआईएसी) के आपातकालीन फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए मध्यस्थता आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया गया था। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमना और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने मामले में फैसला सुनाने का समय सुबह साढ़े दस बजे तय किया है। पीठ ने 11 जनवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था और कहा था कि वह रिलायंस रिटेल को एफआरएल की संपत्ति की बिक्री पर रोक लगाने वाले एसआईएसी के आदेश से संबंधित मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय में वापस भेजना चाहती है। शीर्ष अदालत ने एफसीपीएल (फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड) और एफआरएल (फ्यूचर रिटेल लिमिटेड) द्वारा दायर याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रखा है।

अगले वित्त वर्ष 25,000 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण, 'रोपवे' कार्यक्रम चलाने की भी घोषणा

नयी दिल्ली,

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्गों में 25,000 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल पर राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम चलाने की भी घोषणा की। सीतारमण ने संसद में वर्ष 2022-23 का बजट पेश करते हुए कहा कि लोगों एवं सामान की तीव्र आवाजाही के लिए सरकार एक्सप्रेसवे के बारे में %पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान% भी लेकर आएगी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक संसाधनों को समर्थन देने के लिए सरकार नवाचारी तरीकों से 20,000 करोड़ रुपये जुटाएगी। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण एवं देखरेख मुश्किल होने से रस्सियों से बने मार्ग (रोपवे) पारिस्थितिकीय रूप से टिकाऊ विकल्प के रूप में उभरे हैं। इसके लिए सरकार पीपीपी मॉडल पर राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि रोपवे विकास कार्यक्रम शुरू करने के पीछे पर्वतीय क्षेत्रों में आवाजाही का सुगम मार्ग तैयार करने के अलावा पर्यटन को बढ़ावा देने का भी उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-23 में 60 किलोमीटर की लंबाई वाली कुल आठ रोपवे परियोजनाओं के अनुबंध जारी किए जाएंगे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बजट पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इस साल के बजट ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं किसानों के विकास

को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।

गडकरी ने कहा कि इस बजट ने ढांचागत क्षेत्र को भी प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम से पूर्वोत्तर राज्यों, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एवं कश्मीर के लोग लाभांवित होंगे।

यूएस स्मार्टफोन की चौथी तिमाही में बिक्री रही स्थिर : रिपोर्ट

नई दिल्ली ।

अमेरिकी स्मार्टफोन का कारोबार 2021 की चौथी तिमाही में स्थिर रहा, क्योंकि छुट्टियों के मौसम में प्रीमियम फ्लैगशिप डिवाइसेज की आपूर्ति कम थी। काउंटरपॉइंट रिसर्च के अनुसार, वाहक चैनलों में मजबूत अवकाश प्रचार, आपूर्ति की कमी के कारण बैकऑर्डर, देरी से लॉन्च और कोविड-19 के कारण इन-स्टोर प्रतिबंध तिमाही के प्रमुख आकर्षण रहे। रिसर्च डायरेक्टर जेफ फील्डहॉक ने एक बयान में कहा, ÷2021 की चौथी तिमाही में अमेरिकी स्मार्टफोन बाजार बहुत प्रतिस्पर्धी था। वाहक अपने स्मार्टफोन आधार को बनाए रखने के लिए प्रचार के साथ आक्रामक थे। इसने प्रमुख वाहकों के बीच निरंतर रिकॉर्ड या कम रिकॉर्ड वाले स्मार्टफोन मंथन में योगदान दिया।÷

आईफोन 13 सीरीज की आपूर्ति की मांग के साथ, विशेष रूप से प्रो श्रृंखला मॉडल के लिए एप्पल की बिक्री तिमाही-दर-तिमाही 17 प्रतिशत बढ़ी। आईफोन 13 प्रो और प्रो मैक्स दिसंबर के अधिकांश समय में बैकऑर्डर पर थे, जिसमें प्रतीक्षा समय छह सप्ताह तक था। सैमसंग की बिक्री सालाना आधार पर 11 फीसदी बढ़ी। गैलेक्सी एस21 सीरीज के उपकरणों की कमी और गैलेक्सी एस21 फैन एडीशन के विलंबित लॉन्च सहित कई कारकों ने ब्रांड की बिक्री को रोक दिया।

रिपोर्ट में कहा गया, लेकिन ए-सीरीज के उच्च मिश्रण और फोल्डेबल्स के मजबूत प्रदर्शन ने सैमसंग को साल-दर-साल वृद्धि दर्ज करने में मदद की। फील्डहैक ने नोट किया कि हार्डवेयर बिक्री के लिए विशिष्ट, टी-मोबाइल अमेरिका में सबसे बड़ा स्मार्टफोन चैनल था और मामूली रूप से सालाना वृद्धि हुई। एटीएंडटी तीसरा सबसे बड़ा चैनल था और इसके स्मार्टफोन की मात्रा साल-दर-साल 4 फीसदी से अधिक गिर गई।

सैमसंग गैलेक्सी एस22 सीरीज 9 को होगा लॉन्च

-45वॉट चार्जिंग स्पीड के साथ हो सकता है लॉन्च

नई दिल्ली ।

साउथ कोरिया की कंपनी सैमसंग गैलेक्सी एस22 सीरीज 9 फरवरी को लॉन्च होने वाली है।इस बारे में कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि सैमसंग गैलेक्सी एस22 में 25वॉट चार्जिंग स्पीड दी जाएगी। वहीं, कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि लाइनअप गैलेक्सी एस फ्लैगशिप में 45वॉट की स्पीड दी जा सकती है।

जानकारी के अनुसार, 3सी ने 25वॉट चार्जिंग के साथ सैमसंग गैलेक्सी एस22 (एसएम-एस9010), गैलेक्सी एस22 + (एसएम-एस9060), और गैलेक्सी एस22 अल्ट्रा (एसएम-एस9080) को भी वेरिफाइड किया है। लेकिन डेनमार्क के डेमको ने 45वॉट चार्जिंग के साथ प्लस और अल्ट्रा मॉडल को वेरिफाइड किया है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि गैलेक्सी एस22+ (एसएम/एस906ई/डीएस, एसएम-906ई, एसएम-एस9060) और गैलेक्सी एस22 अल्ट्रा (एसएम-एस908ई/डीएस, एसएम-908ई, एसएम-एस9080, एससी-52सी, एससीजी14) की चार्जिंग स्पीड अलग हो सकती है। हालांकि, इस पर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।

वैनिला मॉडल (एसएम-एस901ई/डीएस, एसएम-901ई, एसएम-एस9010, एससी-51सी, एससीजी13) केवल 25वॉट तक ही जाएगा। डेनिश सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने इन स्मार्टफोन्स की बैटरी का खुलासा तो नहीं किया है। हालांकि, हाल ही में एक लीक से पता चला है कि गैलेक्सी एस22 में 3700 एमएएच की बैटरी दी जा सकती है। जबकि गैलेक्सी एस22+ और गैलेक्सी एस22 अल्ट्रा में क्रमशः 4,500 एमएएच और 5000 एमएएच की बैटरी दी जा सकती है। जानकारी के अनुसार, सैमसंग ने गैलेक्सी एस22 सीरीज के बारे में अभी कुछ नहीं कहा है । लीक के मुताबिक, वैनिला गैलेक्सी एस22 की कीमत 799 डॉलर यानी करीब 59,800 रुपये होने की उम्मीद है। अगर बात करें गैलेक्सी एस22+ की तो इसे 999 डॉलर यानी करीब 74,800 रुपये में लॉन्च किया जा सकता है।

इसके अलावा टॉप-ऑफ-द-लाइन गैलेक्सी एस22 अल्ट्रायूएस में 1,199 डॉलर यानी करीब 89,800 रुपये हो सकती है।

एयरटेल ने एसडी-डब्लूएएन स्टार्टअप लावेल नेटवर्क्स में किया रणनीतिक निवेश, हासिल की 25 फीसदी हिस्सेदारी

नई दिल्ली । यह निवेश एयरटेल बिजनेस के नेटवर्क-एज-अ-सर्विस (एनएएएस) पोर्टफोलियो को बढ़ावा देगा क्योंकि उद्यम अपनी डिजिटल बदलाव के उद्देश्य को हासिल करने के लिए सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क सिस्टम कर रहे हैं स्थापित।

भारत की प्रमुख कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर, भारती एयरटेल ("एयरटेल") ने बेंगलुरु स्थित टेक्नोलॉजी स्टार्टअप, लावेल नेटवर्क्स में लगभग 25% इक्विटी हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए समझौते की घोषणा की है। समझौता लागू वैधानिक अनुमोदन के अधीन है।

पूरी तरह से भारत में शुरू और विकसित हुए लावेल नेटवर्क सॉफ्टवेयर-डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क सॉल्यूशन्स प्रदान करने में विशेषज्ञ है। कंपनी इंडस्ट्रियल सेक्टर में सॉल्यूशन्स की बड़ी श्रृंखला प्रदान करती है। इसके प्लेटफॉर्म ने देश के सबसे बड़े वित्तीय संस्थानों से लेकर ई-कॉमर्स नेटवर्क तक हजारों भारतीय उद्यमों को जोड़ा है।

जैसे-जैसे अधिक से अधिक उद्यम अपने ग्राहकों को डिजिटल-फर्स्ट इको सिस्टम में सेवा देने के लिए क्लाउड आधारित एप्लिकेशन्स के प्रयोग की तरफ बढ़ रहे हैं, उनकी ऑन-डिमांड और विश्वसनीय नेटवर्क कनेक्टिविटी की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। नतीजतन, ऐसे सॉफ्टवेयर डिफाइंड सॉल्यूशन्स की मांग में वृद्धि हुई है जिनमें क्लाउड आधारित हाइब्रिड आईटी वातावरण को सेवाएं प्रदान करने की क्षमता हो।

अपलक घोष, एसोसिएट डायरेक्टर और हेड ऑफ आईसीटी, फ्रॉस्ट एंड सुलिवेन साउथ एशिया बताते हैं, "सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क उद्यमों के लिए इस डिजिटल युग में अपने नेटवर्क के बुनियादी ढांचे को बदलने और सकारात्मक भविष्य सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक टूल है। एफ एंड एस एंड-यूज़र के सर्वे 2021 के अनुसार, भारत में इसका बाजार 2022-2026 में 55% की सीएजीआर से तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। लगभग 62% उद्यमों ने अगले 1-2 वर्षों में अपने संगठन में नई साइट्स और नेटवर्क लागत-दक्षता के लिए एसडी-वैन का उपयोग करने की योजना बनाई है। कुछ प्रमुख कारक हैं, जो इस अभूतपूर्व रणनीति में योगदान देंगे, उनमें हाइब्रिड नेटवर्क की त्वरित स्थापना और निर्बाध प्रबंधन की आवश्यकता शामिल है।"

16 फरवरी से शुरु होंगे रणजी ट्रॉफी मुकाबले

मुम्बई । भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के अनुसार रणजी ट्रॉफी के लीग मुकाबले 16 फरवरी से शुरु होंगें। यह मुकाबले 5 मार्च तक चलेंगे। इससे पहले यह मुकाबले 13 जनवरी से शुरु होने थे पर कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण नहीं हो पाये थे। बीसीसीआई के अनुसार इस टूर्नामेंट में 38 टीम भाग लेंगी और इसके मैच अहमदाबाद, कोलकाता, त्रिवेंद्रम, कटक, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद और राजकोट में खेले जाएंगे। इसके प्रारूप में भी बदलाव किया गया है और इसमें चार टीम के आठ ग्रुप बनाये गये हैं। इसमें प्लेट समूह में छह टीम रहेंगी। देश में जिस प्रकार से संक्रमण के मामले कम हुए हैं उसको देखते हुए ही बोर्ड ने इसके आयोजन का फैसला किया है। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले साल ये मुकाबले नहीं हुए थे। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने हाल ही में कहा था कि इस टूर्नामेंट का आयोजन दो चरणों में होगा। लीग चरण फरवरी और मार्च जबकि नॉकआउट चरण के मैच जून में होंगे। इसका कारण बीच के समय में इंडियान प्रीमियर लीग आईपीएल मैचों का आयोजन है।

खेल बजट 305 करोड़ रुपए बढ़ा : साल दर साल ऐसे आए उतार-चढ़ाव

नई दिल्ली ।

तोक्यो ओलंपिक खेलों में देश की सफलता का प्रभाव खेल बजट में नजर आता है जब केंद्र सरकार ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए तीन हजार 62 करोड़ 60 लाख रुपए आवंटित किए जो पिछले साल की तुलना में 305 करोड़ 58 लाख रुपए अधिक हैं। पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने खेलों के लिए दो हजार 596 करोड़ 14 लाख रुपए आवंटित किए थे जिसे बाद में संशोधित करके दो हजार 757 करोड़ दो लाख रुपए कर दिया गया था। भारत ने तोक्यो ओलंपिक में ट्रैक एवं फील्ड में एतिहासिक स्वर्ण पदक सहित कुल सात पदक जीते। देश में चरणबद्ध तरीके से खेल गतिविधियां बहाल हो गई हैं और बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल तथा हांगझू एशियाई खेलों के रूप में दो वैश्विक प्रतियोगिताओं को देखते हुए 2022 काफी महत्वपूर्ण सत्र है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए शायद सरकार ने खेल गतिविधियों पर अधिक खर्च करने का फैसला किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से मंगलवर को पेश बजट में सरकार की अहम योजना खेलो इंडिया कार्यक्रम में 316 करोड़ 29 लाख रुपये का इजाफा किया गया है। खेल इंडिया कार्यक्रम के लिए पिछले बजट में 657 करोड़ 71 लाख रुपए आवंटित किए गए थे तो अब बढ़कर 974 करोड़ रुपए हो गए हैं। खिलाड़ियों के कुल प्रोत्साहन और पुरस्कार राशि में भी इजाफा किया गया है जो 245 करोड़ से 357 करोड़ रुपए हो गई है। भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) के बजट में सात करोड़ 41 लाख रुपए की कटौती की गई है जो अब 653 करोड़ रुपए होगा। राष्ट्रीय खेल विकास कोष में आवंटन राशि को भी 9 करोड़ रुपए घटाकर 16 करोड़ रुपए कर दिया गया है। राष्ट्रीय सेवा योजना में 118 करोड़ 50 लाख रुपए का भारी भरकम इजाफा किया गया है। इसका आवंटन 283 करोड़ 50 लाख रुपए है। राष्ट्रीय खेल महासंघों के लिए आवंटन को पहले की तरह 280 करोड़ रुपए ही रखा गया है।

पिछले वर्षों के खेल बजट (करोड़ में)

2012-2013 = 1152
2013-2014 = 1219
2014-2015 = 1769
2017-2018 = 1943
2018-2019 = 2197
2019-2020 = 2776
2020-2021 = 2826
(कोविड के कारण खेल इवेंट नहीं हुए तो बजट 1800.15 करोड़ कर दिया गया)
2021-2022 = 2596
2022-2023 = 3062

कांग्रेस के समय खेल बजट (करोड़ में)

2012-2013 = 1152
2013-2014 = 1219

भाजपा के समय खेल बजट (करोड़ में)

2014-2015 = 1769
2017-2018 = 1943
2018-2019 = 2197
2019-2020 = 2776
2020-2021 = 2826
2021-2022 = 2596
2022-2023 = 3062

सचिन तेंदुलकर के बेटे से लेकर बंगाल के मंत्री तक ने भेजा है आईपीएल नीलामी में नाम

स्पोर्ट्स डेस्क ।

आईपीएल के 15वें सीजन के लिए नीलामी की प्रक्रिया 12-13 फरवरी को की जाएगी। इस नीलामी के लिए दुनिया के 590 की खिलाड़ियों की फाइनल लिस्ट भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने तैयार कर ली है। इस नीलामी में जहां बड़े खिलाड़ियों पर ध्यान होगा तो वहीं कुछ ऐसे नाम भी होंगे नीलामी में जो सबको हैरत में डाल देंगे। आईपीएल के मेगा नीलामी के लिए महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर ने भी अपना नाम दिया है। अर्जुन ने अपना बेस प्राइज 20 लाख रुपए रखा है। वह भारत के अनकैप्ड खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हैं। पिछली बार आईपीएल नीलामी में मुंबई इंडियंस ने उन्हें बेस प्राइज पर खरीदा था। वहीं इस लिस्ट में एक मंत्री का नाम भी शामिल है। जी, हां पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री मनोज तिवारी ने भी आईपीएल नीलामी में अपना नाम भेजा है। मनोज तिवारी को पिछले साल हुई आईपीएल नीलामी में किसी भी टीम ने खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। पर शायद खेल मंत्री बनने के बाद उन्हें कोई टीम खरीद ले।आखिरी बार मनोज तिवारी को साल 2018 में पंजाब की टीम ने खरीदा था। उस समय पंजाब की टीम ने मनोज तिवारी को एक करोड़ रुपए में खरीदा था। उसके बाद से मनोज तिवारी को किसी भी टीम ने नहीं खरीदा है।

दर्शकों के बिन ही खेली जाएगी भारत-वेस्टइंडीज एकदिवसीय सीरीज

अहमदाबाद । भारत और मेहमान टीम वेस्टइंडीज के बीच छह से 11 फरवरी तक होने वाली तीन मैचों की एकदिवसीय सीरीज दर्शकों के बिना ही खाली स्टेडियम में खेली जाएगी। गुजरात क्रिकेट संघ (जीसीए) ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए ही दर्शकों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गयी है। सीरीज के सभी तीनों मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाएंगे। जीसीए ने अपने एक बयान में कहा , 'हम वेस्टइंडीज के भारत दौरे पर एकदिवसीय सीरीज की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं , हालांकि यह खाली स्टेडियम में होगी। इसमें छह फरवरी को होने वाला पहला एकदिवसीय मैच एक बहुत ही खास और ऐतिहासिक मैच होगा क्योंकि भारत इस प्रारूप में अपना 1000 वां मुकाबला खेलेगा। वहीं भारतीय टीम दुनिया की पहली क्रिकेट टीम होगी जो इस आंकड़े तक पहुंचेगी।' वहीं दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया ओर तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है। जीसीए ने कहा, ' वर्तमान हालातों को देखते हुए सभी मैच बिना खाली स्टेडियम में खेले जाएंगे क्योंकि किसी प्रकार का जोखिम नहीं लिया जा सकता।' वहीं एकदिवसीय सीरीज के बाद दोनों टीमों कोलकाता में तीन मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज खेलेंगी। इसमें 75 फीसदी दर्शकों को पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवेश की अनुमति दी है।

टाटा स्टील मास्टर्स शतरंज : कार्लसन नें जीता टाटा स्टील मास्टर्स का आठवाँ खिताब

विज्क आन ज़ी, नीदरलैंड (निकलेश जैन)

टाटा स्टील शतरंज 2022 का खिताब रिकॉर्ड आठवीं बार विश्व के नंबर एक शतरंज खिलाड़ी और विश्व शतरंज चैम्पियन नॉर्वे के मेगनस कार्लसन नें अपने नाम कर लिया । कार्लसन नें अंतिम दो राउंड मे यूएसए के फबियानो करूआना और रूस के डेनियल डुबोव के खिलाफ पूरा अंक अर्जित करते हुए 13 राउंड मे कुल 9.5 अंक बनाकर विजेता बनने मे कामयाब रहे । कार्लसन नें इससे पहले टाटा स्टील शतरंज को कभी कोरस शतरंज के नाम से जाना जाता था का खिताब 2008, 2010, 2012, 2015, 2016, 2018 और 2019 मे यह प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया था । कार्लसन के बाद भारत के पूर्व विश्व चैम्पियन विश्वनाथन आनंद का नंबर आता है वो यह खिताब 5 बार अपने नाम कर चुके है । कार्लसन के बाद 8 अंक बनाकर अजरबैजान के ममेद्यारोव और हंगरी के रिचर्ड रापोर्ट 8 अंक बनाकर टाईब्रेक के आधार पर क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे । प्रतियोगिता के पहले भाग मे सबसे आगे चल रहे भारत के विदित गुजराती को अंतिम राउंड मे रूस के सेरगी कार्याकिन से हार का सामना करना पड़ा और अंतिम चार राउंड मे 3 हार और एक ड्रॉ के चलते वो 6 अंक बनाकर 10वे स्थान पर रहे जबकि भारत के युवा खिलाड़ी प्रग्गानंधा आर नें अंतिम राउंड मे रूस के आन्द्रे एसीपेंकों को मात देते हुए 12वां स्थान हासिल किया ।

संक्षिप्त समाचार

आईसीसी वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर मिताली राज

दुबई = भारतीय कप्तान मिताली राज आईसीसी वनडे महिला बल्लेबाजों की रैंकिंग में एक पायदान चढ़कर दूसरे स्थान पर पहुंच गई जबकि तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी दूसरे स्थान पर बनी हुई है। हरफनमौलाओं में भारत की दीप्ति शर्मा एक पायदान चढकर चौथे स्थान पर है। मिताली के 738 रेटिंग अंक है और ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हीली 750 अंक लेकर शीर्ष पर है। भारत की स्मृति मंधाना 710 अंक लेकर छठे स्थान पर बनी हुई है। ऑस्ट्रेलिया की जोनासन गेंदबाजों की रैंकिंग में शीर्ष पर है जिनके 760 अंक है जबकि झूलन के 727 अंक है। ऑस्ट्रेलिया की मेगान शट 717 अंक लेकर तीसरे स्थान पर है। हरफनमौलाओं में इंग्लैंड की नटाली स्किवेर शीर्ष पर है। ऑस्ट्रेलिया की एलिसे पैरी दूसरे और दक्षिण अफ्रीका की मरियाने काप तीसरे स्थान पर है। वेस्टइंडीज की हेली मैथ्यूज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बाद दो पायदान चढकर छठे स्थान पर पहुंच गई है।

शीतकालीन ओलंपिक के लिए आए खिलाड़ियों में तेजी से बढ़ रहे वायरस संक्रमण के मामले

बीजिंग = बीजिंग ओलंपिक के लिए चीन पहुंचने वाले अन्य लोगों की तुलना में एथलीट और टीम के अधिकारियों की कोविड-19 जांच का नतीजा अधिक संख्या में पॉजिटिव आ रहा है। स्थानीय आयोजकों द्वारा मंगलवार को जारी किए गए आंकड़ों में सोमवार को यहां पहुंचे 379 लोगों में से वायरस की चपेट में आने वाले खिलाड़ियों और टीम अधिकारियों की संख्या 16 है। संक्रमण के प्रसार को सीमित करने के लिए उन्हें पृथकवास होटलों में ले जाया गया है। इसमें कई खिलाड़ी अपनी स्पर्धा में भाग लेने से चूक सकते है। ओलंपिक हितधारकों की 0.66त्न की तुलना में एथलीटों और अधिकारियों का पॉजिटिविटी रेट (वायरस जांच में संक्रमित मिलने वालों का प्रतिशत) 4.2त्न है। हितधारकों में स्थानीय कार्यकर्ता और मीडिया भी शामिल है। इस श्रेणी में बीजिंग पहुंचने वाले लोगों की संख्या 1,059 है जिसमें कोरोना वायरस जांच में सात लोगों को पॉजिटिव पाया गया। ओलंपिक के लिए 23 जनवरी से शुरू हुए कोविड-19 जांच में अब तक लगभग 200 पॉजिटिव मामले मिले है। इन में से 67 खिलाड़ी और अधिकारी है। पिछले दो दिनों से हालांकि खिलाड़ी और अधिकारी अधिक संख्या में संक्रमित मिल रहे है।

टीम इंडिया को तय करने की जरूरत, केएल राहुल सलामी बल्लेबाज है या मध्यक्रम के : अगरकर

नई दिल्ली ।

वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी एकदिवसीय श्रृंखला से पहले पूर्व क्रिकेटर अजीत अगरकर ने कहा है कि टीम इंडिया को यह तय करने की जरूरत है कि केएल राहुल लंबे समय तक सलामी बल्लेबाज के रूप में खेलेंगे या मध्यक्रम बल्लेबाज के रूप में खेलेंगे। 29 वर्षीय राहुल ने शिखर धवन के साथ भारत के लिए पारी की शुरुआत की और रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे श्रृंखला में टीम का नेतृत्व भी किया। अगरकर ने कहा कि मुझे लगता है कि उन्हें पहली बात यह तय करने की जरूरत है कि वह एक सलामी बल्लेबाज या मध्य क्रम का बल्लेबाज है क्योंकि वह दक्षिण अफ्रीका में कप्तान था और जो मेरे लिए थोड़ा निराशाजनक था क्योंकि वह नंबर पर इतना सफल नहीं रहा है। 4 या 5 यही वह भूमिका है जिसे वे देख रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं होने जा रहा है तो फिर से आपको अपने निर्णय पर टिके रहना होगा यदि आप एक सलामी बल्लेबाज बनने जा रहे हैं तो आप श्रृंखला में रोहित के साथ पारी की शुरुआत भी कर सकते हैं। इसलिए यह दिलचस्प होगा क्योंकि शिखर धवन भी वहां हैं। अगरकर ने यह भी कहा कि वह धवन के भविष्य के बारे में निश्चित नहीं हैं क्योंकि भारत के पास शीर्ष क्रम में कई विकल्प हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने कहा कि मुझे यकीन नहीं है कि शिखर धवन एक साल या डेढ़ साल में कहां होंगे, भले ही उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रन बनाए हों। आपके पास ईशान किशन या ऋषभ पंत जैसे कुछ विस्फोटक खिलाड़ी हैं। कौन जानता है कि यह काम करेगा या नहीं जिससे उसे शीर्ष क्रम के लिए मौका मिलेगा। भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला 6 फरवरी से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बंद दरवाजों के पीछे खेली जाएगी।

आरिफ खान शीतकालीन ओलंपिक के लिए रवाना

नई दिल्ली । बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेलों में भारत के इकलौते प्रतिनिधि स्कीअर आरिफ खान दल प्रमुख हरजिंदर सिंह और सहयोगी स्टाफ के साथ रवाना हो गए हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरिंदर बत्रा ने सोमवार को रवानगी से पहले उन्हें शुभकामनाएं दी। आरिफ दो स्पर्धाओं में भाग लेंगे और शुक्रवार से शुरू हो रहे खेलों में उनका लक्ष्य शीर्ष 30 में जगह बनाना है। बत्रा ने बताया कि भारतीय टीम 19 फरवरी को लौटेगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में रहने वाले आरिफ बीजिंग में स्लालोम और जाइंट स्लालोम वर्ग में भाग लेंगे जो 13 और 16 फरवरी को खेली जाएगी। 31 वर्ष के आरिफ ने सापोरो में 2017 एशियाई शीतकालीन खेलों में भी भाग लिया था। आईओए ने भारतीय आइस हॉकी संघ के महासचिव हरजिंदर को दल प्रमुख के रूप में भेजा है। हाल ही में टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना में जगह बनाने वाले आरिफ ने कहा कि सैंटा कैटरीना में अभ्यास से उन्हें काफी मदद मिली है। उन्होंने कहा, 'मैं कुछ साल से काफी मेहनत कर रहा हूं और शीर्ष 30 में आना भी मेरे लिये पदक की तरह होगा।'

आईपीएल 2022 में गेंदबाजी करने पर बोले हार्दिक- यह सभी के लिए सरप्राइज

अहमदाबाद :

नई आईपीएल फ्रेंचाइजी अहमदाबाद के कप्तान चुने गए स्टार भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने उनके 2022 आईपीएल सीजन में गेंदबाजी करने को लेकर कहा है कि यह सभी के लिए सरप्राइज होगा। हार्दिक ने मंगलार को इस संबंध में सवाल पूछे जाने के जवाब में कहा कि उनकी टीम को पता है कि वह कहां खड़े हैं। उन्होंने इस बारे में सीधा जवाब नहीं दिया, हालांकि उन्होंने अपनी कप्तानी के नजरिए, अपने द्वारा निर्धारित लक्ष्यों और वह अहमदाबाद फ्रेंचाइजी की संस्कृति को कैसे आकार देना चाहते हैं, के बारे में आशावादी होते हुए बातचीत की। राशिद खान, शुभमन गिल, मुख्य कोच आशीष नेहरा और टीम के मेंटर गैरी कर्स्टन के साथ हार्दिक चाहते हैं कि उनका पक्ष नई विरासतों की गाथा लिखे, क्योंकि फ्रेंचाइजी का लक्ष्य ऊंचाइयों को छुना है। हार्दिक ने अपनी नई यात्रा के बारे में बताया, 'हम शून्य से शुरुआत कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हम नई विरासतें बना सकते हैं और नई संस्कृतियां बना सकते हैं जिनका मैं समर्थन करना चाहता हूं। यह एक बहुत ही रोमांचक समय होने जा रहा है।% आईपीएल और भारत के लिए महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा के नेतृत्व में खेलने के बाद हार्दिक ने जोर देकर कहा कि वह वर्षों से प्राप्त ज्ञान को अमल में लाने के इच्छुक हैं। वह अपने साथी टीम मेट्स के बड़े भाई की तरह बनना चाहते हैं, ताकि अगर कोई खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से हतोत्साहित हो तो वह उन पर भरोसा कर सके। अहमदाबाद के कप्तान ने कहा, 'कप्तान बनना सीखने के लिए कोई नियम नहीं है। मैं हमेशा एक ऐसा इंसान रहा हूं जो जिम्मेदारी लेना पसंद करता है और मैं चुनौती के लिए उत्सुक हूं। एक कप्तान के तौर पर मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि सभी खिलाड़ियों को मुझसे पर्याप्त समय मिले। मैंने यही सीखा है और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि मेरे दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले रहें।'

एकल खिलाड़ियों का युगल प्रारूप में खेलना खेल के लिए अच्छा: बोपन्ना

नई दिल्ली ।

भारत के अनुभवी टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने कहा है कि युगल ड्रॉ में एकल खिलाड़ियों की मौजूदगी खेल के लिए अच्छी है क्योंकि इससे अधिक प्रशंसक स्टेडियम में आते हैं और युगल प्रारूप का प्रचार करने में मदद मिलती है। किसी भी टूर्नामेंट में एकल मुकाबले अधिक आकर्षण का केंद्र होते हैं लेकिन दिन-प्रतिदिन युगल प्रारूप भी प्रतिस्पर्धी होता जा रहा है क्योंकि शीर्ष एकल खिलाड़ी भी इसमें खेल रहे हैं और इससे युगल मुकाबले अधिक रोमांचक और कड़े हो रहे हैं। प्रवेश के लिए जब सिर्फ युगल रैंकिंग पर विचार किया जाता था तो युगल खिलाड़ियों को दबदबा था। लेकिन एकल रैंकिंग पर भी गौर करने से शीर्ष एकल खिलाड़ी भी युगल मुकाबले खेलने लगे हैं जिससे युगल खिलाड़ियों के लिए दबदबा बनाए रखना मुश्किल हो गया है। बोपन्ना ने कहा कि निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि यह अच्छा है या बुरा लेकिन एकल खिलाड़ियों की मौजूदगी से फायदे की स्थिति होती है। यह पूछने पर कि क्या यह बेहतर नहीं होगा कि इस प्रारूप में सिर्फ युगल विशेषज्ञों को खेलने की स्वीकृति मिले, बोपन्ना ने कहा कि यह अजीब स्थिति है। काफी एकल खिलाड़ी अपने खेल में सुधार के लिए युगल मुकाबले खेलते हैं। (डेनिस) शापोवालोव (बोपन्ना के जोड़ीदार) को युगल मुकाबले खेलना पसंद हैं और साथ ही साथ वह काफी कुछ सीख रहे हैं, चाहे रिटर्न में सटीकता हो या वॉली या रिटर्न, जिससे उसे एकल में काफी मदद मिलती है। आज मुझे पता है कि सभी टूर्नामेंट के लिए प्रवेश लगातार मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि काफी एकल खिलाड़ी भी युगल मुकाबले खेल रहे हैं। भारत के शीर्ष युगल खिलाड़ी ने कहा कि युगल खिलाड़ियों के लिए यह शानदार रहेगा अगर पुराना नियम लागू हो जाए जिसमें सिर्फ युगल रैंकिंग पर विचार किया जाता था लेकिन यह बदलाव नहीं होना वाला। यही कारण है कि शीर्ष स्तर पर खेलते हुए रैंकिंग बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण है, अन्यथा 500 और 1000 स्तर के टूर्नामेंट में जगह बनाना मुश्किल हो जाएगा। बोपन्ना टाटा ओपन महाराष्ट्र में हमवतन रामकुमार रामनाथन के साथ चुनौती पेश करेंगे। अतीत में इस मुद्दे पर बहस हो चुकी है जब युगल खिलाड़ियों को लगता था कि एकल खिलाड़ी उनकी जगह ले रहे हैं।

अब मुख्य बल्लेबाज के रुप में अधिक योगदान दे सकता हूं : विराट

नेतृत्व कर्ता बनने कप्तान होना जरुरी नहीं

नई दिल्ली । भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने कहा है कि अब वह टीम के मुख्य बल्लेबाज के रूप में और अधिक योगदान दे सकते हैं। विराट ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में मिली हार के बाद ही टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ दी है। कोहली ने कहा कि सभी चीजों का एक कार्यकाल और समय होता है। इसलिए आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। लोग कह सकते हैं कि 'इस आदमी ने यह क्या कर दिया पर आपको पता है कि जब आप आगे बढ़ने तथा और अधिक उपलब्धियां हासिल करने के बारे में सोचते हो तो आपको फैसले लेने पड़ते हैं। अब बल्लेबाज के रूप में शायद आप टीम के लिए अधिक योगदान दे सकते हो। आप टीम को अधिक जीत दिला सकते हो। इसलिए इस पर गर्व कीजिए। साथ ही कहा कि लीडर होने के लिए आपको कप्तान होने की जरूरत नहीं है। यह सामान्य सी बात है। उन्होंने कहा कि जब महेंद्र सिंह धोनी कप्तान नहीं थे तब भी हम उनके पास सलाह लेने के लिए जाया करते थे। इसलिए कप्तान के रुप में मैंने अपना काम कर दिया था और अब उससे आगे बढ़ने की जरुरत है। आगे बढ़ने का फैसला करना भी नेतृत्वक्षमता का हिस्सा है, समझना होगा कि इसका सही समय होता है। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा को उनकी जगह सीमित ओवरों के प्रारूप में भारतीय टीम की कप्तानी सौंपी गई है हालांकि बोर्ड ने टेस्ट फॉर्मेट में उनके उत्तराधिकारी की घोषणा अभी नहीं की है।

केंद्र सरकार का यह बजट आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने वाला लोकरंजक बजट है: मुख्यमंत्री

अहमदाबाद । मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के वर्ष 2022-23 के आम बजट को 'आत्मनिर्भर भारत' के संकल्प को संपूर्ण रूप से साकार करने वाला बजट करार दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट का स्वागत करते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह सर्वसमावेशी, सर्वपोषक और लोकरंजक बजट है। मुख्यमंत्री ने बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के दौरान देश के नागरिकों को मुफ्त वैक्सीन, जरूरतमंदों को मुफ्त राशन और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि जैसे स्वास्थ्य संबंधित अनेक उपायों का लाभ देने के बावजूद केंद्र सरकार ने जनता पर एक भी रुपए का अतिरिक्त कर बोझ डाले बिना यह बजट पेश किया है। कोरोना महामारी के प्रभाव से समूची अर्थव्यवस्था को तेजी से उबारने के लिए युवाओं, महिलाओं, किसान, विद्यार्थी, व्यवसायी और नियोक्ताओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ग्रामीणों सहित सभी के सर्वग्राही विकास और उत्थान की प्रतिबद्धता वाले इस बजट के लिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के अमृत पर्व वर्ष का यह 'अमृत बजट' अगले 25 वर्ष के 'अमृत काल' पर अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने की नींव रखने वाला बजट है। इस बजट में भारत की आजादी के 75 से 100 साल पूरे होने तक की यात्रा का ब्लू प्रिंट और विकास का रोडमैप है। उन्होंने आगे कहा कि इस बजट में पीएम गति शक्ति, सर्वसमावेशक विकास, उत्पादकता वृद्धि और निवेश के अवसर जैसी चार

प्राथमिकताओं पर विशेष जोर दिया गया है। इस बजट में पीएम गतिशक्ति प्रोजेक्ट के तहत देश एवं राज्य के विकास की गति को रफ्तार देने का ध्येय निहित है। उन्होंने कहा कि गुजरात 'पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट' को लागू करने के मामले में अग्रणी रहा है और अभी भी देश में सबसे आगे रहने को संकल्पबद्ध है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि स्थानीय व्यवसायों एवं आपूर्ति श्रृंखलाओं की सहायता के लिए 'वन स्टेशन, वन प्रोडक्ट' का दृष्टिकोण लोकप्रिय बनेगा। पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आगामी एक वर्ष में 80 लाख घरों का निर्माण होने से लोगों का खुद के घर का सपना साकार होगा। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना के तहत आगामी पांच वर्षों में 60 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार होने से आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना साकार होगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल क्रांति के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने के साथ ही 'पीएम ई-विद्या' योजना के अंतर्गत एक कक्षा-एक टीवी चैनल कार्यक्रम से सभी राज्यों के पहली से लेकर 12वीं तक की कक्षाओं में प्रादेशिक भाषाओं में पूरक शिक्षा दी जा सकेगी। अभी सहकारी मंडलियों को 18.5 की दर से न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) का भुगतान करना पड़ता है, जिसे घटाकर 15 फीसदी किया गया है। इसी तरह, 1 से 10 करोड़ रुपए तक की आय वाली सहकारी समितियों पर लगने वाले अधिभार यानी सरचार्ज की मौजूदा 12 फीसदी की दर को घटाकर 7 फीसदी कर दिया गया है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं देश के पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह को हृदय से धन्यवाद दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फसल के मूल्यांकन और भूमि अभिलेखों के डिजिटाइजेशन में किसान ड्रोन के उपयोग की पहल को गुजरात में भी क्रियान्वित करेंगे। इस बजट में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का जो संकल्प किया गया है, उसे गुजरात में सफलतापूर्वक अमलीजामा पहनाने की शुरुआत हो चुकी है।

बजट 2022 स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी केंद्रित

नए युग की शुरुआत हो चुकी तब टेक्नोलॉजी की ओर आगे बढ़ रहा है इसकी झांकी आज के बजट में देखने मिली है। बीते दो सालों से बजट टेबलेट के जरिए पेश किया जा रहा है। यहीं बात अंगूली निर्देश करती है की नया युग टेक्नो केंद्रित और डिजिटल आधारित होगा। वित्त मंत्री ने मंगलवार को पेश किए बजट में कृषि क्षेत्र पर तो फोकस किया गया है। सस्ता हाउसिंग, 5 जी टेलीकॉम, इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी, टेक्नोलॉजी , रोजगार सृजन , शिक्षा और स्वास्थ के साथ संरक्षण क्षेत्र पर जोर दिया गया है। साथ ही पीएम गति शक्ति योजना पर विशेष जोर दिया गया है। उत्पादकता वृद्धि के साथ निवेश बढ़ाने पर भी फोकस किया गया है।

– प्रतीक तोशनीवाल, स्टार्टअप इन्वेस्टर, सलाहकार

कोरोना के दौर में केन्द्र सरकार का बजट ऊंट के मुंह में जीरा : अर्जुन मोढवाडिया

अहमदाबाद ।

केन्द्र सरकार के आज पेश किए गए बजट को लेकर गुजरात प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रमुख अर्जुन मोढवाडिया की प्रतिक्रिया सामने आई है। केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा लोकसभा में पेश 2022-23 के बजट को मोढवाडिया ने कोरोना के विकट दौर में ऊंट के मुंह में जीरा करार दिया और कहा कि बजट को लेकर अपेक्षा थी कि ठप हो चुके अर्थतंत्र को रफ्तार मिलेगी, महंगाई उन्मूलन और रोजगार के अवसरों के सृजन की घोषणा की जाएगी। लेकिन इन सभी आशाओं पर केन्द्रीय बजट ने पानी फेर दिया है। मोढवाडिया ने कहा कि केवल कॉर्पोरेट सेक्टर के पूंजीपति लोगों को टेक्स में राहत दी गई है, परंतु जीएसटी की 1.40 लाख करोड़ रुपए की ऐतिहासिक आय के बावजूद आयकर में कोई राहत नहीं देकर मध्यम वर्ग को बड़ा झटका दिया है। बजट में किसानों के लिए एमएसपी के प्रावधाव और आय बढ़े इसकी घोषणाओं की उम्मीद थी, उसमें भी निराशा हाथ लगी है। जीवनजरूरी चीजवस्तुओं पर जीएसटी स्लैब करने की उम्मीदों पर भी पानी फिर गया है। अर्जुन मोढवाडिया ने कहा कि यह बजट आम आदमी के लिए कटोरा दरखास्त के समान है। कोरोना में मारे गए लोगों के परिवार को सहायता के लिए रु. 4 लाख के मुआवजे के ऐलान की अपेक्षा की जा रही है, वह भी आज के बजट में पूरी नहीं हुई। वृद्धों के लिए आजीविका के साधन सामग्री ब्याजदर में भी कोई वृद्धि नहीं की गई। राज्य सरकारों का सहायता के बजाए लोन देने का प्रावधान किया गया है। बाजार में मांग पैदा करने या छोटे उद्योगों के विकास के लिए कोई प्रावधान बजट में नहीं है। विदेशी यूनिवर्सिटी को न्यौता देकर देश में शिक्षा महंगी करने का

प्रावधान किया गया है। शहरी विकास के लिए उच्चस्तरीय समिति बनाकर देश के 50 प्रतिशत को शहरी क्षेत्र में शामिल कर गांवों को खत्म करने का प्रयास किया गया है। मोढवाडिया ने कहा कि कुल मिलाकर आंकड़ों की मायाजाल रचकर फूल गुलाबी सपने दिखाए गए हैं, परंतु वास्तविकता में ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई कि जिससे महंगाई कम हो या बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले या गरीब, मध्यम वर्ग के लोगों को राहत मिले।

अनिल कुमार लाहोटी ने पश्चिम रेलवे के महा प्रबंधक का अतिरिक्तस कार्यभार ग्रहण किया

अहमदाबाद । मध्यी रेल के महाप्रबंधक अनिल कुमार लाहोटी ने मंगलवार, 1 फरवरी, 2022 को पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक का अतिरिक्त् कार्यभार ग्रहण कर लिया है। लाहोटी ने आईआईटी रुड़की (पूर्व रुड़की विश्वविद्यालय) से मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग (स्ट्रक्चर) की डिग्री प्राप्तक की है। वे भारतीय रेलवे सेवा इंजीनियर (IRSE) के 1984 बैच के वरिष्ठ अधिकारी हैं। अनिल कुमार लाहोटी को रेलवे में विविध पदों पर कार्य करने का गहन अनुभव प्राप्त है। इन्होंने मध्य रेल से अपनी रेल सेवा शुरु की और नागपुर, जबलपुर (अब पश्चिम मध्य रेलवे पर) और भुसावल मंडल और मध्य रेल मुख्यालय में 1988 से 2001 तक विभिन्न पदों पर काम किया है। इन्होंने सदस्य इंजीनियरिंग, रेलवे बोर्ड के विशेष कार्यकारी अधिकारी, मुख्य इंजीनियर (निर्माण), उत्तर रेलवे, कार्यकारी निदेशक (ट्रैक मशीन), रेलवे बोर्ड और उत्तर मध्य रेलवे के प्रधान मुख्य इंजीनियर के रूप में भी काम किया है। मध्यस रेल के महाप्रबंधक का कार्यभार संभालने से पूर्व श्री लाहोटी उत्तनर रेलवे में मुख्या प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) के पद पर कार्यरत थे। आपने नई दिल्ली स्टेशन को विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित करने की योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें भूमि और एअर स्पेयस का वाणिज्यिक विकास और सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल का विकास शामिल है। आपने दिल्ली में भीड़भाड़ कम करने के लिए आनंद विहार में दिल्ली में एक नए दिशात्मक टर्मिनल तथा नई दिल्लीं स्टे्शन के महत्व पूर्ण द्वितीय प्रवेशद्वार की योजना बनाई और निर्माण किया।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण), मुख्य इंजीनियर (निर्माण) के पदों पर कार्य करते हुए आपने नई रेल लाइनों, दोहरीकरण, यार्ड रिमॉडलिंग और् महत्वपूर्ण पुलों के निर्माण जैसी ढांचागत परियोजनाओं का क्रियान्वलयन किया। अनिल कुमार लाहोटी, रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक सिविल इंजीनियरिंग (योजना) के रूप में संरक्षा, रखरखाव, पुनर्वास और स्थायी मार्ग के उन्नयन, उच्च एक्स ल भार और ट्रैक पर उच्च गति के संचालन पर नीति तैयार करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। ट्रैक रखरखाव मानदंडों पर समिति के सदस्य के रूप में, ट्रैक रखरखाव व्यवस्था को कुशल और प्रभावी बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक माप के आधार पर ट्रैक रखरखाव के लिए उद्देश्य रखरखाव मानदंड पर एक उद्देश्य नीति विकसित करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने ट्रैक रखरखाव के मशीनीकरण और स्वचालन में बड़े पैमाने पर काम किया है और भारतीय रेलवे पर ट्रैक रखरखाव के पूर्ण मशीनीकरण के लिए एक व्यापक मास्टर प्लान तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मंडल रेल प्रबंधक, लखनऊ के रूप में, इन्होंने लखनऊ मंडल पर यात्री और माल ढुलाई संचालन और बुनियादी ढांचे के उन्नयन से संबंधित कई चुनौतियों का सामना किया।

अहमदाबाद मंडल पर फिर गूंजी छुक-छुक की आवाज व स्टीम इंजन की किलकारी

अहमदाबाद । पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल पर अहमदाबाद स्टेशन, साबरमती स्टेशन तथा डीआरएम ऑफिस में संरक्षित रखे गए हेरिटेज स्टीम लोकोमोटिव इंजन जो कभी भारतीय रेलवे की पटरी पर शासन करते थे। इन इंजनों का नवीनीकरण किया गया है, जिसमें आकर्षक कलर,वास्तविक संचालन की हूबहू स्मॉक एवं साउंड सिस्टम तथा मरम्मत कर स्थापित किया गया है। अहमदाबाद स्टेशन पर प्रदर्शित नैरोगेज हेरिटेज स्टीम लोको इंजन 587 W जिसे च्अतीत गौरवज्ज के नाम से जाना जाता है, जो इंग्लैंड में W. G. बंगाल लिमिटेड कास्टल इंजीनियरिंग वर्क्स द्वारा 1937 में बनाया गया था। साबरमती स्टेशन पर प्रदर्शित मीटर गेज हेरिटेज स्टीम लोको 3430 YG है, जिसे "शांतिदूत" के नाम से जाना जाता है। जो 1963 में टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी द्वारा निर्मित स्टैंडर्ड फ्रेट लोको है। जो 40 मील प्रति घंटे तक की रफ्तार से दौडा करता था। डीआरएम ऑफिस में प्रदर्शित नैरोगेज हेरिटेज स्टीम लोको 548 ष्ठ है जिसे "प्रगति" के नाम से जाना जाता है। जिसका निर्माण निप्पॉन शरयो सेजों कैशल कॉ. लिमिटेड जापान द्वारा 1957 में बनाया गया था। 73 वे गणतंत्र दिवस (26 जनवरी 2022) की पूर्व संध्या पर मंडल रेल प्रबंधक तरुण जैन की डिजायर एवं इनविजन के अनुसार वरिष्ठ मंडल मैकेनिकल इंजीनियर, अभिषेक कुमार सिंह के मार्गदर्शन में मेकेनिकल विभाग, मंडल दुर्घटना राहत ट्रेन कांकरिया के कर्मचारियों द्वारा इन संरक्षित हेरिटेज स्टीम इंजीनों का नवीनीकरण किया गया है।

नवीनीकरण गतिविधियों में शामिल है

- भारी मात्रा में जंग लगी चादरों की मरम्मत करना एवं सुंदर रंग योजन के साथ आकर्षक पेंट करना।
- स्टीम इंजनों की सीटी और ऑरिजनल कार्य पैटर्न की तर्ज पर स्टीम इंजन वर्किंग साउंड सिस्टम की स्थापना।
- घने वाष्प/धुआँ के समान दिखने वाले स्मोक को उत्सर्जित करने के लिए ग्लिसरीन आधारित डिवाइस की स्थापना।
- साउंड और स्मोक सिस्टम को टाइम वेस्ड ऑटोरन सिस्टम के साथ एकीकृत करना।

- अहमदाबाद और साबरमती स्टेशन पर प्रातः 09:00 से 11:00 बजे तथा शाम को 18:00 से 23:00 बजे तक प्रति/घंटे 2 मिनट के लिए स्मोक और साउंड सिस्टम को प्रोग्रामिंग किया गया है।
- इसी प्रकार डीआरएम ऑफिस में प्रातः 9:00,10:00, दोपहर 12:30, 13:00, 13:30 शाम 17:00 और 18:00 बजे प्रति/घंटे 2 मिनट के लिए स्मोक और साउंड सिस्टम को प्रोग्रामिंग किया गया है।

विजिटर्स और यात्री अब स्टीम इंजनों के आकर्षण, साइट्स एवं साउंड का आनंद ले सकेंगे, जो कभी भारत में एक सदी से भी अधिक समय तक राज करते रहे थे।

काल बनकर दौड़ रही बस ने वृद्ध को रौंदा, गुस्साए लोगों ने वाहनों में तोड़फोड़ और आगजनी की

भरुच।

भरुच के शेरपुरा गांव के निकट तेज रफ्तार में दौड़ रही बस ने एक वृद्ध को रौंद दिया। इस घटना में वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से गुस्साए आसपास के लोगों ने कई वाहनों में तोड़फोड़ की और दो बसों में आग लगा दी। घटनास्थल पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस टीम ने हालात पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक भरुच शहर के निकट शेरपुरा निवासी करीब 65 वर्षीय इस्माइल आदमभाई मांचवाला सोमवार की देर रात यात्रियों को उतारने के बाद शेरपुरा स्टेन्ड के निकट बस को खड़ी कर नीचे उतर रहे थे। उस वक्त दहेज की ओर से आ रही दूसरी बस ने इस्माइल मांचवाला को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में सिर और शरीर में कई जगह

गंभीर चोट लगने से वृद्ध की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना से गुस्साए आसपास के लोगों में आक्रोश भड़क उठा और दुर्घटना को अंजाम देकर भाग रहे बस को रोक लिया। गुस्साए लोगों ने बस में तोड़फोड़ शुरू कर दी और उसमें आग लगा दी। इतना ही नहीं वहां से गुजर रहे अन्य वाहनों में भी तोड़फोड़ और आगजनी की। सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई और गुस्साए लोगों को तितर बितर कर हालात पर काबू पाया। हांलाकि तब तक आग बस में जलकर एक ढांचे में तब्दील हो चुकी थी। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज आगे की कार्रवाई शुरू की।

वित्त वर्ष 2022 की तीसरी तिमाही में टीसीआई का शानदार प्रदर्शन, वार्षिक आधार पर कर पश्चोत लाभ (पीएटी) में 94% और एबिटा में 36% की वृद्धि

भारत की अग्रणी एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला और लॉजिस्टिक्स समाधान प्रदाता कंपनी ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ("टीसीआई") ने आज 31 दिसंबर 2021 को समाप्त होने वाली तीसरी तिमाही के लिए अपने वित्तीय नतीजों की घोषणा कर दी है। सेमीकंडक्टर की कमी के कारण ऑटोमोटिव क्षेत्र में बाधाओं के बावजूद त्योहारी सीजन ने विकास में बढ़ोतरी की है। मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स ने प्रगति हासिल करना जारी रखा और विशेष रूप से हमारे तटीय शिपिंग व्यवसाय ने असाधारण प्रदर्शन किया। टीसीआई मल्टी-मॉडल व्यवसाय में निवेश के साथ बना हुआ है क्योंकि इसका जीएचजी उत्सर्जन में कमी पर सीधा असर पड़ता है, जिससे हमारे सभी ग्राहकों के लिए सकारात्मक ईएसजी अनुपालन होता है।

हम पूर्ति और ग्राहक सेवा के लिए तकनीकी सक्षम प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स और कोल्ड सप्लाई चेन सॉल्यूशंस की मांग में लगातार वृद्धि देख रहे हैं।

एकीकृत

वित्तीय नतीजों के मुख्य आंकड़ें वित्त वर्ष 2022 की तीसरी तिमाही बनाम वित्त वर्ष 2021 की तीसरी तिमाही

- परिचालन से राजस्व 759 करोड़ रुपये रहा, सालाना आधार 6.2% और तिमाही आधार पर 3.1त्न की वृद्धि
- वित्त वर्ष 2021 की तीसरी तिमाही के मुकाबले 114 करोड़ रुपये का एबिटा
- वित्त वर्ष 21 की तीसरी तिमाही के 11.6% के मुकाबले एबिटा मार्जिन 14.9% रहा
- वित्त वर्ष 21 की तीसरी तिमाही के 40 करोड़ रुपये के मुकाबले 94% के इजाफे के साथ 78 करोड़ रुपये का कर पश्चीत लाभ
- वित्त वर्ष 2021 की तीसरी तिमाही के 5.5% के मुकाबले पीएटी मार्जिन 10.1% रहा।

वित्तीय नतीजों के मुख्य आंकड़ें वित्त वर्ष 2022 के पहले 9 महीनों बनाम वित्त वर्ष 2021 के पहले 9 महीने

- परिचालन से राजस्व 2359 करोड़ रुपये, सालाना आधार पर 23.5त्न की वृद्धि
- वित्त वर्ष 2021 के 9 महीनों के 197 करोड़ रुपये के मुकाबले 320 करोड़ रुपये का एबिटा
- वित्त वर्ष 2021 के 9 महीनों के 10.2त्न के मुकाबले 13.5त्न का एबिटा मार्जिन
- वित्त वर्ष 2021 के 9 महीनों के 85 करोड़ रुपये के मुकाबले 143त्न के इजाफे के साथ कर पश्चाति लाभ (पीएटी) 206 करोड़ रुपये

गुजरात में कोरोना के फिर बढ़े मामले, 8 338 नए मरीज, 16629 हुए ठीक, 38 मौतें

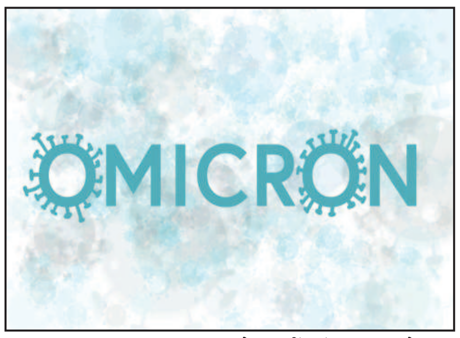

अहमदाबाद।

गुजरात में सोमवार के मुकाबले मंगलवार को कोरोना के दैनिक केसों की संख्या में वृद्धि हुई है। सोमवार को राज्य में कोरोना के 6679 नए केस दर्ज हुए थे, वहीं मंगलवार को यह संख्या बढ़कर 8338 हो गई। हांलाकि कोरोना से स्वस्थ होने का दर बढ़ रहा है, लेकिन मृतांक थम नहीं रहा। आज राज्यभर में कोरोना से 38 मरीजों की मौत हो गई। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने का दर 92.65 प्रतिशत है। मंगलवार को राज्य में 4.49 लाख से ज्यादा नागरिकों का टीकाकरण किया गया। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अहमदाबाद कॉर्पोरेशन में 2654, वडोदरा कॉर्पोरेशन में 1712, वडोदरा में 484, राजकोट कॉर्पोरेशन में 475, सूरत कॉर्पोरेशन में 257, पाटन में 224, गांधीनगर कॉर्पोरेशन में 223, बनासकांठा में 212, कच्छ में 210, राजकोट में 160, भरुच में 145, सूरत में 13।, मेहसाणा में 130, मोरबी में 116, खेडा में 112, पंचमहल में 98, आणंद में 95, जामनगर कॉर्पोरेशन में 95, साबरकांठा में 84, वलसाड में 81, भावनगर कॉर्पोरेशन में 80, गांधीनगर कॉर्पोरेशन में 64, अमरेली में 61, अहमदाबाद में 48, जूनागढ़ कॉर्पोरेशन में 46, नवसारी में 39, गिर सोमनाथ में 3।, सुरेन्द्रनगर में 37, तापी में 34, दाहोद में 33, जूनागढ़ में 30, जामनगर में 21, छोटाउदेपुर में 16, देवभूमि द्वारका में 16, महीसागर में 16, डांग में 13, नर्मदा में 11, अरवल्ली में 10, बोटाद में 5 और पोरबंदर में 5 समेत राज्यभर में कोरोना के 8338 नए केस दर्ज हुए। जबकि 16629 लोगों को डिस्चार्ज किए जाने के साथ ही राज्य में अब तक 108 3022 नागरिक कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं। मंगलवार को राज्य में 38 मरीजों की मौत के साथ राज्य में कोरोना का मृतांक 10511 पर पहुंच गया। फिलहाल राज्य में ।5464 एक्टिव केसों में ।5235 स्टेबल हैं और 229 मरीज वेन्टीलेटर पर हैं। मंगलवार को राज्य में 449165 नागरिकों के टीकाकरण के साथ राज्य में अब तक कुल 9 करोड़ 83 लाख 82 हजार 401 लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है।

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, सम्पादकः संजय रमाशंकर मिश्रा द्वारा ११४, न्यू प्रियंका टाउनशीप अपार्टमेन्ट, डिंडोली, उधना, सुरत (गुजरात) प्रिन्टर्स- भूनेश्वरा प्रिन्टर्स, प्लाट नं. 29, परमानन्द इण्डस्ट्रीयल सोसायटी, चौकसी मील के पास, उधना मगदल्ला रोड़ (गुजरात) से मुद्रित एवं ११४, न्यू प्रियंका टाउनशीप अपार्टमेन्ट, डिंडोली, उधना, सूरत (गुजरात) से प्रकाशित। कार्यालय फोनः 0261-2274271, (न्यायिक क्षेत्र सूरत रहेगा)